नवसर्जन संस्कृति

RNI No. GJHIN/25/A2786
NAVSARJAN SANSKRUTI

नवसर्जन संस्कृति

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 01
अंक : 034
दि. 06.11.2025,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

EDITOR : JIGNESHKUMAR PETHABHAI VAGHELA Regd. Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Centre, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad-382 424, Gujarat, India.

Phone : 76983 33307 (M) 84859 51747, 70963 33307 ● Email : navsarjansanskruti2016@gmail.com ● Email : navsarjansanskruti2016@yahoo.com ● Website : www.navsarjansanskruti.com

बिहार चुनाव का पहला रण : 18 जिलों की 121 सीटों पर आज मतदाता तय करेंगे सियासी भविष्य, 1,314 उम्मीदवार मैदान में

(जीएनएस)। पटना। बिहार की राजनीति में आज एक बार फिर लोकतंत्र का उत्सव शुरू होने जा रहा है। 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा, जो आगामी विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय करने में निर्णायक साबित हो सकता है। इस चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर वोट डाले जाएंगे और कुल 1,314 उम्मीदवार मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इन उम्मीदवारों में से कई हाई-प्रोफाइल चेहरे हैं, जिन पर पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं। दिलचस्प यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के 16 मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी इसी चरण में दांव पर लगी है।

चुनाव आयोग के अनुसार, पहले चरण में मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, सीवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, नालंदा, पटना, भोजपुर और बक्सर जिलों में मतदान कराया जाएगा। कुल 3.75 करोड़ मतदाता लोकतंत्र के इस पर्व में भाग लेंगे, जिनमें 1.98 करोड़ पुरुष, 1.76 करोड़ महिलाएं और 758 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। 45,341 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं ताकि मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण रहे।

राजनीतिक समीकरणों की बात करें तो महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (RJD) 72 सीटों, कांग्रेस 24 और वामदलों की तीनों पार्टियां 14 सीटों पर मैदान में हैं। वहीं, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में जनता दल यूनाइटेड (JDU) 57, भाजपा 48, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) 13 और राष्ट्रीय लोक मोर्चा (RLM) 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) एक और AIMIM आठ सीटों पर किस्मत आजमा रही हैं। इस बार जन सुराज आंदोलन के तहत प्रशांत किशोर की पार्टी ने भी 119 उम्मीदवार उतारे हैं, जिससे मुकाबला कई सीटों पर त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। इस चरण में कई चर्चित सीटें हैं — जैसे बक्सर से पूर्व IPS आनंद मिश्रा, परसा से पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा राय की पोती करिश्मा राय, लालगंज से अनु शुक्ला की बेटी शिवानी शुक्ला, छपरा से भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव, अलीनगर से लोकगायिका मैथिली ठाकुर और सीवान से दिवंगत मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब मैदान में हैं। मोकामा में अनंत सिंह और महुआ में तेजप्रताप यादव की सीटें भी चर्चाओं में हैं।

उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय, जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी, राजस्व मंत्री संजय सरावगी और नगर विकास मंत्री जिवेश मिश्रा सहित कुल 16 मंत्रियों के राजनीतिक भविष्य पर जनता की मुहर लगेगी। इन 121 सीटों पर औसतन 11 उम्मीदवार मुकाबले में हैं। मुजफ्फरपुर और कुढ़नी में सबसे अधिक 20-20 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। चुनाव आयोग के आंकड़े बताते हैं कि 40 प्रतिशत उम्मीदवार करोड़पति हैं और औसतन एक प्रत्याशी की संपत्ति 3.26 करोड़ रुपये है। मुंगेर से भाजपा प्रत्याशी कुमार प्रणय 170 करोड़ की संपत्ति के साथ सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जबकि 32 प्रतिशत उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। करीब 50 प्रतिशत प्रत्याशी स्नातक या उससे अधिक शिक्षित हैं, जिससे यह चुनाव आर्थिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टि से दिलचस्प बन गया है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह चरण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए परीक्षा की घड़ी है। 2020 के चुनाव में जेडीयू ने जिन 43 सीटों पर जीत हासिल की थी, उनमें से 23 इसी चरण में थीं। महागठबंधन के लिए भी यह चरण अहम है, क्योंकि पिछली बार उसे इन 121 सीटों में से 61 पर जीत मिली थी। इस बार तेजस्वी यादव राघोपुर से चुनाव मैदान में हैं, और उन पर न केवल अपनी जीत की हैट्रिक बनाने बल्कि गठबंधन की नैया पार लगाने का भी दबाव है।

2020 के आंकड़ों के अनुसार, पहले चरण की 121 सीटों में से RJD को 42, भाजपा को 32, JDU को 27, कांग्रेस को 2 और वीआईपी को 4 सीटें मिली थीं। जबकि LJP को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी। यही कारण है कि इस बार सभी दलों के लिए यह चरण सियासी प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है।

आज का मतदान बिहार के राजनीतिक भविष्य का पहला संकेत देगा — यह बताएगा कि जनता विकास, रोजगार और सुशासन के वादों पर भरोसा करती है या बदलाव की लहर को प्राथमिकता देती है। लोकतंत्र का यह पहला रण बिहार की सियासत की तस्वीर को तय करने वाला साबित हो सकता है।

कालमेघी तूफान से फिलीपींस में तबाही, 66 शव बरामद और सैकड़ों लापता, लाखों लोग बेघर

(जीएनएस)। मनीला। दक्षिण-पूर्व एशियाई देश फिलीपींस इस समय भीषण प्राकृतिक आपदा से जूझ रहा है। उष्णकटिबंधीय तूफान 'कालमेघी' ने मंगलवार को तट से टकराते ही विनाश का ऐसा तांडव मचाया कि अब तक 66 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि सैकड़ों लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन ने देश के कई हिस्सों को तबाह कर दिया है, जिससे हालात बेहद गंभीर हो गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमसी) के अनुसार, उत्तरी लुजॉन क्षेत्र तूफान से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है। यहां दर्जनों गांव नदियों के उफान और पहाड़ी ढलानों से आए मलबे की चपेट में आ गए। राहत दलों को जगह-जगह फंसे लोगों तक पहुंचने में भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शुरुआत में प्रशासन ने 50 मौतों की पुष्टि की थी, लेकिन जैसे-जैसे राहत और खोज अभियान आगे बढ़ा, मृतकों की संख्या बढ़कर 66 तक पहुंच गई।

तूफान की हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा तक दर्ज की गई, जिससे सैकड़ों पेड़ और बिजली के खंभे धराशायी हो गए। कई पुल और सड़कें टूटने से पूरे इलाके का संपर्क व्यवस्था चरमरा गया है। फिलीपींस के उत्तरी इलाकों में हजारों घर बह गए या क्षतिग्रस्त हो गए हैं, और गांवों में खाने-पीने की वस्तुओं की भारी कमी हो गई है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, करीब 20 लाख लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर पलायन कर चुके हैं। अनेक लोग अस्थायी शिविरों में रह रहे हैं, जबकि सैकड़ों परिवार अब भी ऊंची जगहों पर फंसे हुए हैं और सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बिजली, पानी और संचार सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुई हैं, जिससे राहत कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। देश के राष्ट्रपति फर्डिनैंड मार्कोस जूनियर ने आपातकाल की घोषणा करते हुए कहा कि "यह हमारे देश के लिए एक बड़ी त्रासदी है। सरकार सभी संसाधनों को झोंककर राहत और बचाव कार्यों में लगी हुई है, ताकि हर प्रभावित परिवार तक मदद पहुंच सके।" उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से सहायता की अपील भी की है।

संयुक्त राष्ट्र, रेड क्रॉस और कई वैश्विक राहत एजेंसियों ने फिलीपींस को तुरंत मदद भेजनी शुरू कर दी है। हजारों टन खाद्य सामग्री, दवाएं और अस्थायी आश्रय के लिए तिरपाल भेजे जा रहे हैं। यूएन राहत समन्वयक ने कहा है कि आने वाले दिनों में सबसे बड़ी चुनौती स्वच्छ पेयजल, चिकित्सा सहायता और पुनर्वास कार्यों की होगी। 'कालमेघी' तूफान को मौसम विशेषज्ञों ने श्रेणी 3 का शक्तिशाली तूफान बताया है। फिलीपींस हर साल कई उष्णकटिबंधीय तूफानों का सामना करता है, लेकिन 'कालमेघी' ने जिस तरह से जनजीवन को तहस-नहस किया है, उसने 2013 के 'हैयान' तूफान की भयावह यादें ताजा कर दी हैं। राहतकर्मी लगातार मलबे में लापता लोगों की तलाश कर रहे हैं, जबकि मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि कुछ क्षेत्रों में अगले 48 घंटे तक भारी बारिश जारी रह सकती है।

महादेव ऐप घोटाला: रवि उप्पल दुबई से लापता, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी, ईडी को गिरफ्तारी का आदेश

(जीएनएस)। नई दिल्ली। महादेव सट्टेबाजी ऐप से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की ठगी के मुख्य आरोपी रवि उप्पल के दुबई से फरार होने के मामले ने देश की सबसे बड़ी अदालत को नाराज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को रवि उप्पल का पता लगाने और उसे गिरफ्तार करने का स्पष्ट निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि सफेदपोश अपराधियों को अदालतों और जांच एजेंसियों के साथ खेल खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती।

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा कि रवि उप्पल कानून से बचते हुए देश की न्यायिक प्रणाली और एजेंसियों को चुनौती दे रहा है। पीठ ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, "यह अदालत के विवेक को झकझोरता है। अब कुछ करना ही होगा।"

ठिकाने का अब तक कोई पता नहीं

दिसंबर 2023 में दुबई में गिरफ्तारी के बाद माना जा रहा था कि जल्द ही रवि उप्पल को भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा। लेकिन दो साल बीत जाने के बावजूद उसका कोई सुराग नहीं मिला है। सूत्रों के अनुसार, भारतीय एजेंसियों को सूचना मिली है कि उप्पल यूएई से किसी अज्ञात देश चला गया है और उसकी वर्तमान लोकेशन साझा नहीं की गई है। इसके साथ ही यूएई ने प्रत्यर्पण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव रखा है। इस वजह से आरोपी की भारत वापसी अभी तक नहीं हो पाई है।

महादेव ऐप घोटाले का परिचय

महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप घोटाले की शुरुआत 2018 में हुई थी। इस अवैध नेटवर्क के जरिए रोजाना करोड़ों रुपए का सट्टा लगाया जाता था। जांच एजेंसियों के अनुसार, देशभर में इसके करीब 3,200 पैनल सक्रिय थे। यह नेटवर्क दुबई, छत्तीसगढ़, मलेशिया और थाईलैंड में चल रहे कॉल सेंटरों से संचालित किया जा रहा था। घोटाले के मामले में लाखों भारतीय प्रभावित हुए। आरोप है कि लाखों लोगों को इसमें फंसाकर भारी रकम की ठगी की गई। प्रवर्तन निदेशालय ने मामले में कई भारतीय और विदेशी व्यक्तियों की गिरफ्तारी की कार्रवाई की है, लेकिन मुख्य आरोपी रवि उप्पल की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है।

सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी और कार्रवाई की संभावना

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि रवि उप्पल जैसे अपराधियों को अदालतों और जांच एजेंसियों के साथ खिलवाड़ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अदालत ने ईडी से कहा कि वह किसी भी माध्यम से उप्पल का पता लगाकर उसे भारत लाए। न्यायालय की यह चेतावनी इस मामले को उच्च प्राथमिकता देने और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग सुनिश्चित करने की दिशा में एक कड़ा संदेश है।

विशेषज्ञों के अनुसार, महादेव ऐप घोटाला भारत में ऑनलाइन सट्टेबाजी और साइबर अपराध के मामलों की गंभीरता को उजागर करता है। दो साल से फरार मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी न होने से देशभर में न्यायिक प्रक्रिया और एजेंसियों की क्षमता पर सवाल उठे हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की सख्त कार्रवाई से उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही आरोपी को भारत लाकर क़ानून के कटघरे में लाया जाएगा।

हिमाचल में सड़क हादसों में आई बड़ी गिरावट, इस साल अब तक सिर्फ 1,457 दुर्घटनाएं दर्ज — सरकार के प्रयासों से सड़कों पर लौटी सुरक्षा की उम्मीद

(जीएनएस)। शिमला। हिमाचल प्रदेश में सड़क सुरक्षा को लेकर सरकार के निरंतर और सख्त प्रयास अब रंग ला रहे हैं। राज्य में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या पिछले दो वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से घट गई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में अब तक केवल 1,457 सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं, जबकि 2023 में यह संख्या 2,253 थी। यह गिरावट बताती है कि राज्य में सड़क सुरक्षा के मोर्चे पर एक ठोस और स्थायी सुधार देखने को मिल रहा है।

प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यह उपलब्धि हिमाचल जैसे भौगोलिक रूप से कठिन और पहाड़ी राज्य में हासिल करना आसान नहीं था। यहां हर साल भूस्खलन, बादल फटना, बर्फबारी और संकरी घुमावदार सड़कों के कारण वाहन चलाना चुनौती भरा होता है। इसके बावजूद सरकार ने सड़क इंजीनियरिंग, ट्रैफिक प्रबंधन और लोगों में जनजागरूकता बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया, जिसका असर अब स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है।

प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू स्वयं इस अभियान की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को निर्देश दिए हैं कि सड़क सुरक्षा को सिर्फ एक प्रशासनिक कार्य न माना जाए, बल्कि इसे जनता की सुरक्षा और जीवन से जुड़ी सर्वोच्च प्राथमिकता के रूप में देखा जाए।

सरकार ने हाल के वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं। ब्लैक स्पॉट्स की पहचान, सड़क किनारे चेतावनी संकेतों की संख्या बढ़ाना, खतरनाक मोड़ों पर रेलिंग लगाना, चालकों के लिए नियमित सेफ ड्राइविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, और पर्यटन सीज़न में ट्रैफिक पुलिस की अतिरिक्त तैनाती जैसे उपायों ने बड़े पैमाने पर फर्क डाला है।

वर्ष 2024 में जहां कुल 2,147 सड़क हादसे हुए थे, वहीं 2025 में उसी अवधि में यह आंकड़ा घटकर 1,457 पर आ गया — यानी लगभग 32 प्रतिशत की कमी। यह गिरावट न सिर्फ सरकारी नीतियों की सफलता का प्रमाण है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि आम जनता में अब सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ रही है।

दिलचस्प बात यह है कि यह प्रगति ऐसे समय में हुई है जब राज्य को पिछले दो वर्षों में भारी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ा। बारिश, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं ने कई सड़कों को नुकसान पहुंचाया, लेकिन सरकार ने त्वरित मरम्मत और यातायात बहाली पर जोर देते हुए सड़क सुरक्षा ढांचे को मजबूत बनाए रखा।

राज्य के परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, आने वाले महीनों में "स्मार्ट रोड सेफ्टी नेटवर्क" लागू किया जाएगा, जिसके तहत हाईवे और प्रमुख सड़कों पर सेंसर आधारित ट्रैफिक मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया जाएगा। इसके जरिए तेज रफ्तार, गलत दिशा में वाहन चलाने और ओवरलोडिंग पर स्वतः चालान जारी होंगे।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा है कि "हर नागरिक का जीवन अनमोल है। हमारी सरकार का लक्ष्य केवल सड़कें बनाना नहीं, बल्कि उन्हें पूरी तरह सुरक्षित बनाना है। हिमाचल की सड़कें जितनी खूबसूरत हैं, उतनी ही सुरक्षित भी बनें — यही हमारा संकल्प है।"

सत्य साई बाबा जन्म शताब्दी समारोह में 140 देशों के भक्त होंगे शामिल, पीएम मोदी और उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन भी रहेंगे उपस्थित

(जीएनएस)। पुट्टपर्थी। श्री सत्य साई बाबा के जन्म की शताब्दी वर्ष के अवसर पर पुट्टपर्थी एक बार फिर भक्ति और अध्यात्म के महासंगम का केंद्र बनने जा रहा है। 13 से 24 नवंबर तक चलने वाले इस विराट समारोह में विश्वभर के लगभग 140 देशों से श्रद्धालु पहुंचेंगे। यह आयोजन न केवल भारत की आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक बनेगा, बल्कि साई बाबा के "सर्व धर्म समभाव" और "मानव सेवा ही माधव सेवा" के संदेश को वैश्विक स्तर पर पुनः पुष्ट करेगा।

कार्यक्रम में देश के शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति रहेगी। उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दोनों इस भव्य समारोह में सम्मिलित होंगे। प्रधानमंत्री के आगमन के मद्देनज़र कार्यक्रम स्थल — प्रशांति निलयम और आसपास के क्षेत्रों में तीव्र गति से पुनर्विकास कार्य चल रहे हैं। सड़कों, आवासीय क्षेत्रों और सभा-स्थलों को नया रूप दिया जा रहा है ताकि लाखों की संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

श्री सत्य साई सेंट्रल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी आर. जे. रत्नाकर ने बताया कि यह आयोजन केवल एक स्मृति समारोह नहीं, बल्कि "साई मिशन" के प्रति नव-प्रतिबद्धता का क्षण है। उन्होंने कहा कि साई बाबा के आदर्शों — प्रेम, करुणा, सत्य और सेवा — को पुनः अपनाने का यह अवसर विश्व के लिए एक नैतिक और आध्यात्मिक प्रेरणा बनेगा। श्रद्धालुओं के लिए विशाल स्तर पर निःशुल्क भोजन और आवास की व्यवस्था की गई है। अस्थायी टेंट सिटी, मेडिकल सहायता केंद्र, जल व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को अभूतपूर्व पैमाने पर सुदृढ़ किया गया है। आयोजन समिति के अनुसार, प्रतिदिन हजारों की संख्या में भक्त भजन, ध्यान, प्रवचन और सेवा कार्यक्रमों में भाग लेंगे।

इस समारोह में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, जापान, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, नेपाल, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका और खाड़ी देशों सहित 140 देशों से साई भक्त भाग ले रहे हैं। इनमें कई अंतरराष्ट्रीय साई संगठन प्रमुख और सेवा दल भी सम्मिलित होंगे। पुट्टपर्थी के नागरिकों में इस आयोजन को लेकर गहरी आस्था और उत्साह है। शहर के प्रत्येक मार्ग को सजा दिया गया है और साई भक्ति गीतों की गूंज वातावरण को पवित्र बना रही है। कई देशों के प्रतिनिधि समूह सांस्कृतिक प्रस्तुतियों और सेवा परियोजनाओं की झांकी भी प्रस्तुत करेंगे, जिससे साई बाबा के वैश्विक संदेश — "Love All, Serve All" — को मूर्त रूप दिया जा सके। ट्रस्ट के अनुसार, यह आयोजन केवल धार्मिक नहीं बल्कि मानवीय एकता का उत्सव है। साई बाबा के जीवन दर्शन को जीवंत बनाए रखने का यह अवसर भारत की उस सांस्कृतिक विरासत का स्मरण कराता है जहाँ श्रद्धा और सेवा एक-दूसरे का पर्याय हैं। पुट्टपर्थी एक बार फिर उस अनंत ज्योति से आलोकित होने जा रहा है, जिसे स्वयं साई बाबा ने प्रज्वलित किया था — एक ऐसी ज्योति जो किसी धर्म, जाति या सीमा में बंधी नहीं, बल्कि समस्त मानवता के लिए प्रकाश स्रोत है।

संपादकीय

अमीरों की समृद्धि में भी भारी वृद्धि

उदारीकरण व वैश्वीकरण के दौर के बाद पूरी दुनिया में आर्थिक असमानता अपने चरम पर जा पहुंची है। एक तरफ लोग मूलभूत सुविधाओं के अभाव में सड़कों पर उतर रहे हैं तो दूसरी ओर अमीर से और अमीर होते लोगों की विलासिता के किस्से तमाम हैं। जिस बात की पुष्टि स्वतंत्र विशेषज्ञों के जी-20 पैनल द्वारा किए एक अध्ययन के निष्कर्षों में की गई है। इस अध्ययन के अनुसार, वर्तमान में वैश्विक स्तर पर असमानता भयावह स्तर तक जा पहुंची है। आंकड़े बताते हैं कि वर्ष 2000 और 2024 के बीच दुनिया भर में बनी नई संपत्तियों का बड़ा हिस्सा दुनिया के सबसे अमीर एक प्रतिशत लोगों के पास है। जबकि निचले स्तर की आधी आबादी के हिस्से में एक प्रतिशत ही आया है। निस्संदेह, भारत भी इस स्थिति में अपवाद नहीं है। देश के सबसे अमीर एक फीसदी लोगों ने केवल दो दशक में अपनी संपत्ति में 62 फीसदी की वृद्धि की है। दुनिया की इस चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में अमीर लगातार अमीर होते जा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर गरीब गुरबत के दलदल से बाहर आने के लिए छटपटा रहे हैं। इस आर्थिक असमानता का ही नतीजा है कि अमीर व गरीब के बीच संसाधनों का असमान वितरण और बदतर स्थिति में पहुंच गया है। निस्संदेह, पैनल की हालिया रिपोर्ट नीति-निर्माताओं को असमानता के इस बढ़ते अंतर को पाटने के तरीके तलाशने और नये साधन खोजने के लिये प्रेरित करेगी। पिछले ही हफ्ते, केरल सरकार ने दावा किया था कि राज्य ने अत्यधिक गरीब तबके की गरीबी का उन्मूलन कर दिया है। हालांकि, कुछ विशेषज्ञों ने इन दावों को लेकर संदेह जताया है। वहीं दूसरी ओर राज्य के विपक्ष ने भी इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। लेकिन इसके बावजूद राज्य में जन-केंद्रित विकास और सामुदायिक भागीदारी के लाभों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह, इस पहल ने हजारों अत्यंत गरीब परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य सेवा और आजीविका के बेहतर साधनों तक पहुंचने में मदद की है। इसमें दो राय नहीं कि यदि सरकारें वोट बैंक की राजनीति से इतर ईमानदारी से पहले करें तो गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक पहल की जा सकती है। चुनाव से पहले मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की तेजी से बढ़ती प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। यह एक हकीकत है कि कोई भी सुविधा मुफ्त नहीं हो सकती। इस तरह की लोकलुभावनी कोशिशों से राज्यों का वित्तीय घाटा ही प्रभावित होता है। जिसकी कीमत लोगों को विकास योजनाओं से दूर रहकर ही चुकानी पड़ती है। जनता को मुफ्त में सुविधाएं देने के बजाय ऋण व अनुदान से उत्पादकता बढ़ाकर उन्हें स्वावलंबी बनाना होगा। प्रत्येक चिन्हित गरीब परिवार के लिए सूक्ष्म योजनाएं तैयार करना और उन्हें क्रियान्वित करना उचित होगा। निस्संदेह, देश के अन्य राज्य भी अपनी जरूरतों और परिस्थितियों के अनुसार केरल के मॉडल को अपना सकते हैं। इसमें केंद्र व राज्य सरकारों को अनुकूल आंकड़ों का सहारा लेना भी जरूरी होगा। इस साल की शुरुआत में, विश्व बैंक ने बताया था कि भारत 2011-12 और 2022-23 के बीच 17 करोड़ लोगों को गरीबी की दलदल से बाहर निकालने में सफल रहा है। केंद्र सरकार ने अपने काम के लिये खुद की पीठ भी थपथपाई थी। हालांकि, गरीबी के अनुमानों की रिपोर्टिंग की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठाये गए थे। निर्विवाद रूप से सभी हितधारकों को यह तथ्य समझना होगा कि केवल संख्याएं ही पूरी तस्वीर को नहीं उकेर सकती हैं। गरीबी कम करने के प्रयासों के दावों के मुताबिक जमीनी स्तर पर गुणात्मक बदलाव नजर भी आना चाहिए। हालांकि, अर्थशास्त्री आमतौर पर संपत्ति कर लगाने के पक्षधर नहीं होते हैं, लेकिन सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अति-धनी लोग सरकारी खजाने में अपना उचित योगदान दें। अब चाहे कोई अमीर हो या गरीब, सबका ध्यान विकास पर केंद्रित किया जाना चाहिए। तभी देश उत्पादकता के क्षेत्र में आगे बढ़कर गरीबी उन्मूलन की दिशा में सार्थक प्रगति कर सकता है। यह पहल ही विकसित भारत के सपने को साकार करने में मददगार साबित हो सकती है।

लापता हुई आम सहमति की राजनीति, सत्तापक्ष और विपक्ष में नहीं दिखती अब एकमत की राजनीति

> आम सहमति की राजनीति के अभाव का मतलब है राजनीतिक वर्ग के बीच हर मामले में तनाव और तकरार। यह स्थिति पक्ष-विपक्ष के दलगत हित पूरे कर सकती है, देश के हितों का संधान हर्गिज नहीं कर सकती।

चुनाव आयोग की ओर से कल से नौ राज्यों और तीन केंद्रशासित प्रदेशों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआइआर शुरू कर दिया गया। इसी के साथ उसके विरोध में उठी आवाजें मुखर होनी शुरू हो गईं। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार इस प्रक्रिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। आने वाले समय में कुछ और लोग एसआइआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते दिख सकते हैं। इनमें केरल और पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ नेताओं के साथ स्वयं को लोकतंत्र का प्रहरी कहने वाले लोग भी हो सकते हैं। हालांकि बिहार में एसआइआर के विरोध में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने वालों को मुंह की खानी पड़ी। तमाम दलीलों एवं दुष्प्रचार के बावजूद ऐसे लोग सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह सिद्ध नहीं कर सके कि बिहार में एसआइआर के नाम पर कुछ खास वोटरों के नाम इस इरादे से काटे जा रहे हैं कि भाजपा को चुनावी लाभ मिल सके। विपक्षी दलों और उनके समर्थकों की ओर से एसआइआर के विरोध में आशंकाएं तो अनगिनत जताई गईं, लेकिन वे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष निराधार साबित हुईं। इसी कारण एसआइआर बिहार में मुद्दा नहीं बन सका। इसके बाद भी तमिलनाडु, केरल और बंगाल जैसे गैर-भाजपा शासित राज्यों में उसका विरोध हो रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने तो उसके खिलाफ विरोध मार्च निकाल दिया। क्या एसआइआर के दूसरे चरण का विरोध इसलिए हो रहा है, क्योंकि इन आरोपों में कुछ सत्यांश है कि इसे भाजपा के इशारे पर किया जा रहा है? यदि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट इस ओर संकेत ही नहीं करता, उस पर रोक भी लगा देता।

एसआइआर का विरोध इस मानसिकता के तहत हो रहा है कि मोदी सरकार के साथ केंद्रीय संस्थाओं की ओर से जो कुछ भी किया जाता है, वह अनुचित-अवैधानिक ही होता है। इसी कारण मोदी सरकार के हर फैसले और यहां तक कि संसद से पारित होकर कानून बनने वाले विधेयकों का विरोध किया जाता है और उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है। इस सिलसिले के थमने के कोई आसार नहीं, क्योंकि सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच की आम सहमति की उस राजनीति का पूरी तरह लोप हो गया है, जो एक समय भारतीय राजनीति का प्रमुख अवयव थी। इसके चलते राष्ट्रीय महत्व के कुछ मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष की ओर से आम सहमति की राजनीति पर चलने की बातें की जाती थीं। आज तो आम सहमति की राजनीति जैसा शब्द भी करीब-करीब प्रचलन से बाहर हो चुका है। इसका स्थान विरोध के लिए विरोध की राजनीति ने ले लिया है। एसआइआर का विरोध इसी राजनीति के तहत हो रहा है।

यह राजनीति इतनी अधिक हावी हो गई है कि कई बार विरोधी दलों की सरकारें केंद्र सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को भी लागू करने में आनाकानी करती हैं। बंगाल ने अविकसित जिलों के विकास की केंद्र की योजना लागू नहीं की है और दिल्ली में आयुष्मान योजना तब लागू हो पाई, जब आम आदमी पार्टी सत्ता से बाहर हो गई। जब वह दिल्ली की सत्ता में थी तो उसने पीएमश्री योजना में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। इन्कार करने वालों में पंजाब और बंगाल भी थे। स्कूलों को उन्नत करने वाली केंद्र की इस योजना में शामिल होने के अपने फैसले को पिछले दिनों केरल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, क्योंकि सरकार में शामिल भाकपा को यह रास नहीं आया। इसकी भी अनदेखी न की जाए कि कई राज्यों ने नई शिक्षा नीति को अपनाने के बजाय उसे खारिज करने का फैसला किया है।

अब उन मुद्दों पर भी आम सहमति की राजनीति करने की कोशिश होती भी नहीं दिखती, जिन पर यह माना जाता था कि वे पक्ष-विपक्ष के नहीं, देश के मुद्दे होते हैं। उदाहरणस्वरूप विदेश और रक्षा नीति के कुछ बड़े मसलों पर आम सहमति की राजनीति अपनाई जाती थी। अब इनसे जुड़े मामलों पर ऐसा नहीं होता। आपरेशन सिंदूर के दौरान चंद दिन के लिए ही पक्ष-विपक्ष एकजुट दिखा, लेकिन यह सैन्य अभियान स्थगित होते ही दोनों पक्ष एक-दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए। कुछ विपक्षी नेताओं ने सरकार के साथ सेना पर भी निशाना साधने में संकोच नहीं किया। ऐसा ही गलवन घाटी में चीनी सैनिकों से खूनी झड़प के समय भी देखने को मिला था। राहुल गांधी यह दोहराते ही रहते हैं कि मोदी चीनी राष्ट्रपति और अमेरिकी राष्ट्रपति से डरते हैं। मोदी जब एससीओ सम्मेलन में भाग लेने चीन गए तो विपक्ष ने सवाल उठाए। हाल में जब तालिबान विदेश मंत्री भारत आए तो सरकार की अफगान नीति को सवालों के घेरे में खड़ा किया गया।

अभी यह स्पष्ट नहीं कि अमेरिका से व्यापार समझौता कब होगा, पर यह साफ है कि वह जब भी होगा, तब विपक्ष उसे लेकर सरकार को कठघरे में खड़ा करेगा। इसके प्रति सुनिश्चित हुआ जा सकता है कि जब भी यह समझौता होगा, कम से कम कांग्रेस की ओर से यह अवश्य कहा जाएगा कि मोदी ने ट्रंप के समक्ष समर्पण कर दिया। जब विदेश और रक्षा नीति से जुड़े विषय भी दलगत राजनीतिक मतभेदों की भेंट चढ़ जा रहे हों, तब फिर इसकी कल्पना नहीं की जा सकती कि राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय महत्व के अन्य विषयों पर एकजुटता या आम सहमति देखने को मिल सकती है। आम सहमति की राजनीति के अभाव का मतलब है राजनीतिक वर्ग के बीच हर मामले में तनाव और तकरार। यह स्थिति पक्ष-विपक्ष के दलगत हित पूरे कर सकती है, देश के हितों का संधान हर्गिज नहीं कर सकती।

प्रेरणा

क्रांति की सार्थकताः जब सरदार वल्लभभाई पटेल ने युवाओं को सच्ची क्रांति का अर्थ समझाया

भारत का स्वतंत्रता संग्राम केवल अंग्रेज़ों से युद्ध का इतिहास नहीं है, बल्कि वह आत्मा की चेतना, विचारों की जागृति और समाज के पुनर्जन्म की कथा है। इस संघर्ष में कुछ ऐसे महापुरुष हुए जिन्होंने शब्दों से नहीं, बल्कि अपने व्यक्तित्व की दृढ़ता से लाखों लोगों के हृदयों में क्रांति की ज्योति जलाई। उन्हीं में से एक थे — सरदार वल्लभभाई पटेल, भारत के लौहपुरुष। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि क्रांति का अर्थ केवल तलवार उठाना नहीं, बल्कि अपने भीतर की कायरता, अंधविश्वास और जड़ सोच को त्यागना है।

यह घटना उन्हीं दिनों की है जब पटेल देशभर में जनसभाओं को संबोधित कर रहे थे। उस समय भारत में स्वतंत्रता की हवा तो थी, लेकिन बहुत से लोग 'क्रांति' शब्द का केवल उत्साहपूर्ण उपयोग कर रहे थे। वे समझते थे कि अंग्रेज़ों के खिलाफ नारे लगाना ही क्रांति है। बिहार की एक विशाल सभा में जब पटेल पहुंचे, तो युवाओं की भीड़ उमड़ पड़ी। चारों ओर "क्रांति की जय!" के नारे लगने लगे। युवाओं की आंखों में चमक थी, उनके सीने गर्व से फूल गए थे। वातावरण में देशभक्ति का उबाल था, लेकिन पटेल के चेहरे पर एक गंभीर शांति थी — वह शांति जो केवल अनुभव, तप और सच्चे राष्ट्रप्रेम से आती है।

उन्होंने मंच पर आकर कुछ क्षणों तक भीड़ को देखा, फिर धीरे-धीरे बोले — "आप सब 'क्रांति की जय' बोल रहे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रांति का अर्थ क्या है?" यह प्रश्न किसी बिजली की तरह सभा में गूंजा। क्षणभर पहले जोश में चिल्लाने वाले युवा अब शांत हो गए। सबकी निगाहें पटेल पर टिक गईं। उन्होंने पुनः कहा, "एक बार क्रांति करके दिखाइए, फिर उसकी जय बोलिए। जिसका अस्तित्व ही न हो, उसकी जय-जयकार करने से क्या लाभ?" सभा में खामोशी छा गई। यह वाक्य जैसे हर व्यक्ति के हृदय में उतर गया। एक युवा ने साहस कर पूछा, "सरदार साहब, क्या हमारे देश में कभी क्रांति नहीं हुई?" पटेल मुस्कुराए। उनके चेहरे पर अनुभव की रेखाएं और आंखों में करुणा झलक रही थी। उन्होंने कहा, "हां, क्रांति हुई है। अवश्य हुई है। लेकिन वह केवल कुछ जगहों पर हुई। चंपारण में जब गांधीजी ने सत्य और अहिंसा के बल पर किसानों के हक के लिए संघर्ष किया, वह सच्ची क्रांति थी। वह कोई रक्तपात नहीं था, वह आत्मबल की विजय थी। उसी चंपारण की क्रांति ने भारत को दुनिया के सामने नई पहचान दी। लेकिन अफसोस, ऐसी क्रांति अभी पूरे देश में नहीं फैली। कुछ स्थानों पर लोग जागे, कुछ क्षेत्रों में लोग लड़ाई के लिए उठे, लेकिन सम्पूर्ण भारत ने अभी तक एक साथ वह ज्वाला नहीं जलाई जो देश को भीतर से बदल दे।"

सभा में सन्नाटा था, परंतु पटेल की वाणी ने सबके हृदय में हलचल मचा दी थी। तभी एक अन्य युवक ने कहा, "तो वह दिन कब आएगा जब पूरा भारत एक स्वर में 'क्रांति की जय' बोलेगा?"

पटेल की आंखों में एक गहरी चमक उभरी। वे बोले — "वह दिन तब आएगा जब आप सब अपने भीतर की जंजीरों को तोड़ देंगे। जब आप केवल दूसरों की बातों पर नहीं, अपने विवेक पर चलना सीखेंगे। जब आप भीड़ में खोने के बजाय, भीड़ को दिशा देने वाले बनेंगे। जब आप अपने भीतर यह ठान लेंगे कि आप अपने जीवन को देश के लिए समर्पित करेंगे — तब सच्ची क्रांति होगी। क्रांति केवल सरकार बदलने का नाम नहीं, बल्कि सोच बदलने का नाम है। क्रांति का अर्थ है — अंधविश्वास के स्थान पर विज्ञान को अपनाना, डर के स्थान पर साहस लाना, और स्वार्थ के स्थान पर राष्ट्रहित को रखना।"

उन्होंने युवाओं की ओर देखा और आगे कहा — "आप सब कहते हैं कि देश स्वतंत्र होना चाहिए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि अगर हम स्वयं ही अपने मन से स्वतंत्र नहीं हैं, तो देश की स्वतंत्रता का क्या अर्थ होगा? यदि हम अपनी कमजोरियों से, आलस्य से, और अंध परंपराओं से बंधे रहेंगे, तो अंग्रेज़ चले भी जाएं, लेकिन गुलामी की जड़ें हमारे भीतर बनी रहेंगी। इसलिए असली क्रांति भीतर से शुरू होती है — मन से, विचार से, कर्म से।"

उनके शब्द सुनकर युवाओं के चेहरों पर आत्ममंथन का भाव उभर आया। एक युवक ने कहा, "सरदार साहब, हम सब देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हमें बताइए, हम क्या करें?"

पटेल ने कहा, "सबसे पहले स्वयं को तैयार कीजिए। अपने चरित्र को ऐसा बनाइए कि देश आप पर गर्व करे। आपके विचारों में सच्चाई हो, आपके कर्मों में ईमानदारी हो। जब हर व्यक्ति अपने कार्यक्षेत्र में सत्य और परिश्रम से काम करेगा, तो वही सबसे बड़ी क्रांति होगी। क्रांति का अर्थ है — किसान का अपनी मिट्टी से प्रेम, शिक्षक का अपनी जिम्मेदारी से निष्ठा, सैनिक का अपने देश से समर्पण, और युवा का अपने कर्तव्यों के प्रति सजग रहना। जब हर भारतीय अपने हिस्से का धर्म निभाएगा, तभी भारत में सच्ची क्रांति आएगी।"

सभा में मौजूद हर युवक की आंखें चमक उठीं। सब एक स्वर में बोले —

"हम अपने अंदर देशप्रेम की भावना को जगाएंगे! हम अपने देश के लिए सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार रहेंगे!" पटेल ने प्रसन्न होकर कहा, "बस, यही है असली क्रांति। जब शब्द नहीं, कर्म बोलते हैं; जब नारे नहीं, संकल्प उठते हैं; जब भय नहीं, बलिदान होता है — तब राष्ट्र अमर होता है। वह दिन दूर नहीं जब यह देश एक स्वर में बोलेगा — 'क्रांति की जय!'"

उस दिन की वह सभा केवल एक भाषण नहीं थी। वह भारत के युवाओं के हृदय में अंकुरित हुई चेतना का बीज थी। पटेल के शब्दों ने हर युवक को यह सोचने पर विवश कर दिया कि क्रांति बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। तलवारों से नहीं, विचारों से लड़ी जाती है। बंदूकों से नहीं, सच्चाई और त्याग से जीती जाती है।

आज जब हम आधुनिक भारत में बैठकर उस प्रसंग को याद करते हैं, तो यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सरदार पटेल का संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है। आज भी हमारे भीतर कई प्रकार की गुलामियां हैं — लालच, भ्रष्टाचार, असमानता, और आत्मकेन्द्रित जीवन। सच्ची क्रांति तभी होगी जब हर नागरिक इन आंतरिक बंधनों को तोड़ेगा और अपने देश के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करेगा। सरदार पटेल ने जिस दिन यह कहा था कि "भीड़ का हिस्सा मत बनो, ऐसा बनो कि जहां खड़े हो जाओ, वहां भीड़ लग जाए," उस दिन उन्होंने हर भारतीय युवक के लिए दिशा तय कर दी थी। यही वह विचार है जो हर युग में, हर पीढ़ी में लागू होता है — कि सच्ची क्रांति न तो नारे में है, न ही प्रदर्शन में, बल्कि उस व्यक्ति में है जो अपने आचरण, परिश्रम और सत्यनिष्ठा से दूसरों के जीवन में प्रकाश भर देता है।

इसलिए जब भी कोई युवा "क्रांति की जय" बोले, तो उसे याद रखना चाहिए कि यह जय किसी काल्पनिक नारे की नहीं, बल्कि उस भीतर जागी हुई चेतना की है — जो समाज को बदलने की क्षमता रखती है। यही है क्रांति की सच्ची सार्थकता, यही है सरदार वल्लभभाई पटेल का अमर संदेश — कि राष्ट्र की स्वतंत्रता शब्दों से नहीं, संकल्प और कर्म से प्राप्त होती है।

नीतीश के लिए निर्णायक बने रहने की चुनौती, इस चुनाव में उनकी कड़ी परीक्षा

कुछ दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने चुनावी सभा में यह एलान किया कि बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर फिलहाल अभी कोई 'वैकेंसी' नहीं है। उनका यह बयान मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को समर्थन के रूप में देखा गया। हालांकि उससे कुछ दिन पहले शाह ने ही कहा था कि मुख्यमंत्री के नाम पर निर्णय नतीजों के बाद होगा। स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री को लेकर राजग की सहयोगी भाजपा में ऊहापोह की स्थिति है, लेकिन यह भी सच है कि नीतीश कुमार ही पूरी चुनावी चर्चा के केंद्र में हैं।

बिहार के राजनीतिक परिदृश्य पर अभी नीतीश कुमार की जदयू तीसरे नंबर पर, लेकिन राज्य की जटिल राजनीति में नीतीश का महत्व इसी से समझा जा सकता है कि 2005 के बाद से उसके बिना राज्य में कोई सरकार नहीं बन पाई। बिहार के सामाजिक-राजनीतिक समीकरणों का संकेत यही है कि शायद इस चुनाव के बाद भी जदयू के बिना नई सरकार नहीं बन पाएगी। विधानसभा में तीसरे स्थान पर पहुंच जाने के बावजूद अगर कोई दल यह कहे कि उसका नेता सत्ता के खेल में इतना अपरिहार्य बना रहता है तो जाहिर है कि वह राज्य की राजनीति में बड़ा ब्रांड बन चुका है।

यह ब्रांड अचानक नहीं बन गया। लालू-राबड़ी राजनीति से असहज जार्ज फर्नांडिस सरीखे समाजवादी नेताओं ने बिहार के सामाजिक समीकरण को ध्यान में रखते हुए यह ब्रांड गढ़ा। मंडल-कमंडल के बीच राजनीतिक ध्रुवीकरण के मद्देनजर लालू के इर्दगिर्द गोलबंद ओबीसी और अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाए बिना ऐसे ब्रांड की स्वीकार्यता नहीं बन सकती थी। उत्तर प्रदेश की तरह बिहार भी अहसास करने लगा था कि सामाजिक न्याय की मलाई चंद दबंग और प्रभावशाली जातियां ही चट कर रही हैं। इसीलिए ईबीसी का नया वोट बैंक तैयार किया गया। कुर्मी समुदाय के साफ छवि वाले शिक्षित नेता नीतीश कुमार को उसका चेहरा बनाया गया।

जनता दल में विभाजन कर अलग समता पार्टी बनाई गई, जिसने भाजपा से गठबंधन किया। लंबे संघर्ष के बाद 2005 में यही बिहार में बदलाव का ब्रांड बनकर उभरा। बेशक ब्रांड नीतीश के शिल्पकार जार्ज थे, लेकिन मार्केटिंग भाजपा ने भी जमकर की। कारण वही कि सामाजिक न्याय के प्रतीकों में से ही किसी एक को आगे किए बिना लालू-राबड़ी राज से बिहार की मुक्ति संभव नहीं थी। नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ओबीसी में भाजपा की स्वीकार्यता बढ़ी है, पर उससे पहले तक बिहार में वह अगड़ों की पार्टी मानी जाती थी, जिससे अल्पसंख्यकों की दूरियां भी जगजाहिर हैं। भाजपा का गणित यही था कि नीतीश के जरिये लालू के ओबीसी-अल्पसंख्यक वोट बैंक में सेंध लगाए बिना बिहार में न तो बदलाव संभव है और न ही उसका भविष्य। लालू-राबड़ी के जंगलराज का चुनावी नारा भी उस बदलाव की हवा में बेहद कारगर साबित हुआ। नई पीढ़ी को लालू-राबड़ी का जंगलराज याद दिलाना पड़ता है, जबकि नीतीश के शासन के सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं। जदयू और भाजपा बिहार की राजनीति में एक-दूसरे के पूरक बने। बेशक इसका शुरुआती लाभ नीतीश को ही मिला और वे बदलाव की राजनीति के नायक बनकर एक बड़ा ब्रांड बन गए। इसका एक बड़ा कारण भाजपा में किसी व्यापक सामाजिक स्वीकार्यता वाले चेहरे का अभाव भी रहा। इधर भाजपा भी पिछले 20 वर्षों के दौरान राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने में सफल रही है। विधानसभा में सीटें और चुनाव में मत-प्रतिशत इसका प्रमाण है, लेकिन ब्रांड नीतीश के आसपास वह अपना कोई चेहरा स्थापित नहीं कर पाई। नीतीश के समक्ष लालू-राबड़ी की राजनीति के प्रतिनिधि अब तेजस्वी यादव हैं। वे अपना परंपरागत 'एम-वाइ' यानी मुस्लिम-यादव वोट बैंक तो काफी हद तक बचाए रखने में सफल रहे, लेकिन ब्रांड नीतीश के जरिये हुई सेंधमारी की भरपाई नहीं कर पाए। बिहार का यही जमीनी सामाजिक-राजनीतिक गणित दो दशक बाद भी ब्रांड नीतीश की सबसे बड़ी ताकत है। इसके बल पर वे चुनावी राजनीति में न सिर्फ जरूरी, बल्कि दोनों बड़े दलों के लिए सत्ता की मजबूरी भी बने हुए हैं। हालांकि विकास के वादों और दावों के आईने में बिहार कहां खड़ा है, इस सवाल का जवाब अब जनता नीतीश से चाहती है। वैसे नीतीश एक नहीं, दो बार पाला बदल कर दोनों गठबंधनों में सरकार का नेतृत्व कर चुके हैं। इसलिए कोई भी उन पर सीधा हमला नहीं बोलता, क्योंकि सरकार में भागीदार तो वे स्वयं भी रहे। नीतीश से भी ज्यादा समय मुख्यमंत्री रहने के रिकार्ड बताते हैं कि अगर सरकार जन आकांक्षाओं पर खरी उतरे तो सत्ता विरोधी भावना अपरिहार्य नहीं है, लेकिन जदयू का गिरता चुनावी ग्राफ कुछ और इशारा कर रहा है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू मात्र 43 सीटों पर सिमट गई। तर्क दिया जाता है कि भाजपा की शह पर चिराग पासवान ने उसमें बड़ी भूमिका निभाई, पर एक स्थापित ब्रांड को इतना जोरदार झटका देने से भी सवाल तो उठते ही हैं, जिनका जवाब शायद इन चुनावों में मिल जाए।

पिछले विधानसभा चुनाव में राजग और महागठबंधन में कड़ा मुकाबला था। राजग 125 सीटें जीत गया था, जबकि महागठबंधन 110 पर अटक गया था। सर्वाधिक साढ़े 23 प्रतिशत वोट राजद को मिले थे, जबकि 19.8 प्रतिशत वोटों के साथ भाजपा दूसरे स्थान पर रही। 15.7 प्रतिशत वोटों के साथ सत्ता संतुलन की चाबी जदयू के हाथ रही। हालांकि नीतीश की बढ़ती उम्र और सेहत को लेकर उठते सवालों के चलते जदयू नेताओं में भी अपने राजनीतिक भविष्य के प्रति चिंता दिखती है। इस चिंता से जदयू के वोट बैंक को इन चुनावों में प्रभावित होने से बचाने की चुनौती नीतीश कुमार के समक्ष है। अच्छी बात यह है कि नीतीश पर व्यक्तिगत आरोप अभी तक कोई नहीं लगा पाया। फिर भी अगर जदयू का वोट बैंक दरका तो सत्ता के खेल में ब्रांड नीतीश का दबदबा भी प्रभावित हो सकता है। बिहार के दो प्रमुख दलों भाजपा और राजद के लिए नीतीश तभी तक जरूरी हैं, जब तक कि सरकार बनाने के लिए मजबूरी बने हुए हैं।

अभियान

भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा बाईं ओर ही क्यों: शिव-चंद्र के रहस्यमय संबंध का दिव्य रहस्य

हिंदू धर्म की रहस्यमयी परंपरा में भगवान शिव का स्वरूप जितना गूढ़ है, उतना ही वह अनंत प्रतीकों और गहरे अर्थों से भरा हुआ है। देवों के देव महादेव का हर अंग, हर आभूषण, हर चिन्ह किसी दार्शनिक सत्य का द्योतक है। उनके गले का सर्प, जटाओं में प्रवाहित गंगा, भस्म से ढका शरीर और मस्तक पर स्थित त्रिनेत्र—ये सभी उनके स्वरूप को असीम गहराई देते हैं। इन्हीं दिव्य प्रतीकों में सबसे मोहक और रहस्यमय है—उनके मस्तक पर बाईं ओर सुशोभित चंद्रमा, जो उन्हें चंद्रशेखर का स्वरूप प्रदान करता है। यह कोई साधारण अलंकरण नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा, भावनात्मक संतुलन और आध्यात्मिक समरसता का संकेत है।

प्राचीन पौराणिक कथाओं के अनुसार, जब समुद्र मंथन हुआ, तब उसके अंत में निकला कालकूट विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण सृष्टि के विनाश का कारण बन सकता था। उस समय भगवान शिव ने करुणा और संरक्षण की भावना से उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष की तीव्रता से उनका कंठ नीलवर्ण हो गया, तभी से उन्हें नीलकंठ कहा गया। किंतु उस विष की उग्रता से उनके शरीर में जो अग्नि उत्पन्न हुई, उसे शांत करने के लिए चंद्रदेव ने उनके मस्तक पर स्थान लिया। चंद्रमा का शीतल प्रकाश, उसकी सोम ऊर्जा और उसकी शांत लहरें शिव की उग्रता को संतुलित करने लगीं। यही वह क्षण था जब संहारक शिव और शीतल चंद्रमा का दिव्य मिलन हुआ—उग्रता और शांति का शाश्वत संयोग।

ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो चंद्रमा मन, भावनाओं और मानसिक संतुलन का प्रतीक है। वहीं शिव वैराग्य, तपस्या और ब्रह्मज्ञान के प्रतीक हैं। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का होना इस बात का द्योतक है कि कठोरता के भीतर भी करुणा और शीतलता का भाव होना आवश्यक है। जैसे सूर्य जीवन को ऊर्जा देता है पर अत्यधिक गर्मी से जलाता भी है, वैसे ही तपस्या यदि करुणा से रहित हो तो विनाशकारी बन जाती है। इसलिए चंद्रमा शिव के मस्तक पर स्थिर होकर हमें यह जीवन-संदेश देता है कि उग्रता में शांति, कठोरता में करुणा और वैराग्य में कोमलता का संतुलन ही सच्चा आध्यात्मिक मार्ग है।

अब प्रश्न उठता है कि चंद्रमा शिव के मस्तक के बाईं ओर ही क्यों हैं, दाहिनी ओर क्यों नहीं?

इसका उत्तर हमें योग और तंत्र के रहस्यों में मिलता है। मनुष्य के शरीर में तीन प्रमुख नाड़ियाँ होती हैं—इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। इड़ा नाड़ी शरीर के बाएँ भाग में स्थित होती है और यह चंद्र ऊर्जा की वाहक मानी जाती है। यह नाड़ी शीतलता, स्थिरता, अंतर्ज्ञान और भावनात्मक संतुलन से जुड़ी होती है। इसके विपरीत, दाहिनी ओर स्थित पिंगला नाड़ी सूर्य की उर्जा, पुरुष तत्व, क्रियाशीलता और उष्णता की प्रतीक होती है। शिव के मस्तक पर चंद्रमा का बाईं ओर होना यही दर्शाता है कि उनके भीतर चंद्र ऊर्जा का प्रभाव है, जो उनकी इड़ा नाड़ी को सक्रिय रखती है। यही कारण है कि वे अत्यंत उग्र होकर भी स्थिर रहते हैं, विनाशक होकर भी करुणामय हैं।

पौराणिक दृष्टि से यह भी कहा गया है कि चंद्रमा स्वयं मां पार्वती का प्रतीक हैं। जिस तरह शिव के शरीर का बायां भाग शक्ति को समर्पित है—जिसे हम अर्धनारीश्वर रूप में देखते हैं—वैसे ही चंद्रमा का बाईं ओर होना उस शक्ति तत्त्व का द्योतक है। चंद्रमा का स्थान यह दर्शाता है कि शिव का वैराग्य भी अधूरा है यदि उसमें शक्ति, यानी स्त्री-ऊर्जा, का संतुलन न हो। शिव और चंद्रमा, शक्ति और शांति, वैराग्य और भावना—ये सभी एक-दूसरे के पूरक हैं।

एक और गहरा अर्थ यह भी है कि चंद्रमा काल (समय) का प्रतीक है। उसका घटता-बढ़ता आकार जीवन की अस्थिरता और परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। जब शिव उसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं, तो वे यह संकेत देते हैं कि वे काल के स्वामी हैं—महाकाल हैं—जिनके लिए समय का उतार-चढ़ाव मात्र एक लहर है। चंद्रमा शिव के सिर पर यह घोषणा करता है कि जो शिव को साध लेता है, उसके लिए समय भी स्थिर हो जाता है।

शिव के मस्तक का बायां हिस्सा केवल शरीर का हिस्सा नहीं, वह भावनाओं और चेतना का केंद्र है। इसलिए चंद्रमा का वहां होना यह भी दर्शाता है कि ब्रह्मांड में हर उग्र ऊर्जा के भीतर भी शांति की संभावना निहित है। चंद्रमा केवल शिव को शीतलता नहीं देता, बल्कि पूरी सृष्टि को संतुलन का संदेश देता है—कि जो व्यक्ति अपने भीतर के "शिव" को जाग्रत करना चाहता है, उसे पहले अपने "चंद्र" को पहचानना होगा, यानी अपने मन, अपनी भावनाओं, अपनी शीतलता को।

इस रहस्य को गहराई से समझें तो भगवान शिव और चंद्रमा का यह संयोग सृष्टि के दो सबसे मूल तत्वों का मिलन है—अग्नि और जल, पुरुष और स्त्री, तप और करुणा, संहार और सृजन। शिव के मस्तक पर बाईं ओर सुशोभित चंद्रमा यह संदेश देता है कि जो व्यक्ति संतुलन को जान लेता है, वही ब्रह्मांड के रहस्यों को समझ पाता है।

इसलिए जब अगली बार आप भगवान शिव की प्रतिमा में उनके मस्तक पर वह उज्ज्वल अर्धचंद्र देखें, तो यह स्मरण रखें—वह केवल एक आभूषण नहीं, बल्कि सृष्टि का संतुलन है; वह शिव की उग्रता को शांत करने वाला करुणा का प्रतीक है; और वह यह कहता है कि जो अपने भीतर के चंद्रमा को स्थिर कर ले, वही शिव के समान शांत और सर्वशक्तिमान बन सकता है।

RNI No. GJHIN/25/A2786 Printed, Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By (1) JIGNESH RASHIKBHAI GAJJAR at Vansh Corporation, A/8, Shayona Golden Estate, Shahibag, Ahmedabad - 380 004 (2) DESAI RAHUL MAHESHBHAI at Bhavani Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002. (3) HADIK MAHESHBHAI DESAI at Bhoomi Offset, Bhatiya Ni Wadi, Opp Kalupur Railway Station, Kalupur, Ahmedabad-380 002 and Published from B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424. Editor : JIGNESHKUMAR PATHABHAI VAGHELA

बीजिंग-मॉस्को साझेदारी को शी जिनपिंग ने बताया वैश्विक स्थिरता की रीढ़, कहा—"यह संबंध विश्व शांति के लिए आवश्यक"

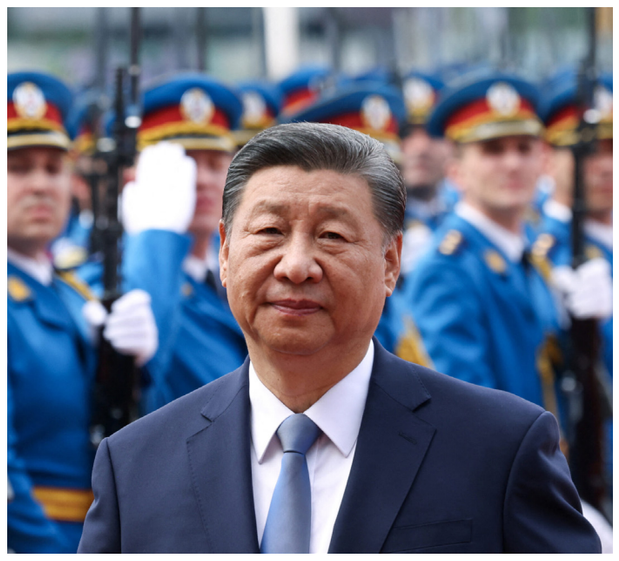

(जीएनएस)। बीजिंग। अंतरराष्ट्रीय मंच पर बढ़ते तनाव और शक्ति-संतुलन के बदलते समीकरणों के बीच चीन और रूस एक बार फिर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े नजर आए। बुधवार को बीजिंग में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन के बीच हुई उच्चस्तरीय बैठक ने इस साझेदारी को और मजबूत करने का संकेत दिया। दोनों नेताओं ने आर्थिक, तकनीकी, ऊर्जा और सुरक्षा सहयोग को गहराई देने के साथ-साथ वैश्विक राजनीति में साझा भूमिका निभाने की प्रतिबद्धता जताई।

बैठक बीजिंग स्थित महलांगोंग रेजिडेंस में हुई, जहां शी जिनपिंग ने मिशुस्तिन का गर्मजोशी से स्वागत किया। चीन की सरकारी एजेंसी शिन्हुआ के अनुसार, शी जिनपिंग ने कहा, "बीजिंग और मॉस्को का सहयोग न केवल दोनों देशों के लिए लाभकारी है, बल्कि यह वैश्विक शांति, स्थिरता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की दिशा में एक आवश्यक तत्व है।" उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीन और रूस का संबंध किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संतुलन बनाए रखने और विकासशील देशों की आवाज को सशक्त करने के लिए है।

शी ने दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को "नए युग की वैश्विक रणनीतिक साझेदारी" बताते हुए कहा कि यह संबंध आज की विश्व राजनीति में "एक ठोस ढाल" की तरह काम कर रहा है। उनके अनुसार, "अमेरिकी एकतरफावाद, पश्चिमी प्रतिबंध और आर्थिक दबावों के दौर में चीन-रूस की एकता एक स्थिर विकल्प प्रस्तुत करती है।"

उन्होंने इस अवसर पर ऊर्जा सुरक्षा, डिजिटल अर्थव्यवस्था, जलवायु परिवर्तन और उन्नत प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। शी ने कहा कि दोनों देशों के बीच साइबेरिया-चीन पाइपलाइन विस्तार, आर्कटिक ऊर्जा परियोजनाएं, और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) में अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में संयुक्त निवेश भविष्य की दिशा तय करेंगे।

रूसी प्रधानमंत्री मिशुस्तिन ने बैठक के दौरान शी जिनपिंग को संबोधित करते हुए कहा कि "रूस, चीन को अपना सबसे विश्वसनीय और दीर्घकालिक साझीदार मानता है।" उन्होंने बताया कि यूक्रेन युद्ध और पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद दोनों देशों के बीच 2024 में व्यापार 240 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया। मिशुस्तिन के शब्दों में, "यह सहयोग राजनीतिक इच्छाशक्ति और परस्पर भरोसे का परिणाम है, जिसे कोई भी दबाव या प्रतिबंध कम नहीं कर सकता।"

बैठक में दोनों नेताओं ने यह भी माना कि वैश्विक मंचों जैसे ब्रिक्स (BRICS), शंघाई सहयोग संगठन (SCO) और संयुक्त राष्ट्र में दोनों देशों का समन्वय दुनिया के दक्षिणी देशों के लिए विकास और शांति का नया मार्ग प्रशस्त कर सकता है।

विश्लेषकों का मानना है कि यह बैठक ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका और यूरोप रूस-चीन गठजोड़ को लेकर पहले से अधिक सतर्क हैं। दोनों देशों की सरकारें अब न केवल आर्थिक रूप से बल्कि राजनयिक और सैन्य स्तर पर भी एक-दूसरे की पूरक भूमिका निभा रही हैं।

बीजिंग में यह स्पष्ट संदेश दिया गया कि चीन और रूस अब "समान दृष्टि" के साथ वैश्विक नेतृत्व में अपनी भूमिका तय करने को तैयार हैं। शी जिनपिंग ने अंत में कहा, "हमारा उद्देश्य टकराव नहीं, सहयोग है — परंतु यदि कोई विश्व संतुलन को चुनौती देगा, तो चीन और रूस मिलकर उसे संभाल लेंगे।"

इस मुलाकात के बाद यह तय हो गया है कि बीजिंग और मॉस्को की साझेदारी केवल क्षेत्रीय नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में वैश्विक शक्ति-संतुलन का निर्णायक स्तंभ बन सकती है।

एअर इंडिया का सर्वर ठप, देशभर में उड़ानें प्रभावित — दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्रियों की भारी भीड़, मैनुअल चेक-इन से बढ़ी अफरातफरी

(जीएनएस)। नई दिल्ली। बुधवार को एअर इंडिया के सर्वर में आई तकनीकी खराबी ने देशभर के यात्रियों की मुश्किलें बढ़ा दीं। दोपहर करीब 3 बजे से एयरलाइन की चेक-इन और लगेज सिस्टम पूरी तरह ठप पड़ गया, जिससे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) सहित देश के अन्य प्रमुख एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की लंबी कतारें लग गईं। सर्वर डाउन होने के कारण एयरलाइन को मजबूरन मैनुअल चेक-इन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी, जिससे उड़ानों के संचालन में भारी देरी देखने को मिली। दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल-2 पर यात्रियों की स्थिति बेहद परेशान करने वाली रही। सैकड़ों लोग हाथों में टिकट और पासपोर्ट लेकर गेट के बाहर खड़े रहे, जबकि कुछ यात्री बुकिंग काउंटरों पर कर्मचारियों से जानकारी मांगते दिखे। एयरलाइन के एक अधिकारी ने पुष्टि करते हुए कहा कि यह समस्या केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के सभी हवाई अड्डों पर एअर इंडिया का सर्वर अस्थायी रूप से ठप पड़ा है। उन्होंने आश्वासन दिया कि तकनीकी दल समस्या को ठीक करने में जुटा है और सिस्टम को जल्द बहाल कर दिया जाएगा।

इस बीच कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर एयर इंडिया की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। यात्रियों का कहना था कि न तो एयरलाइन की ओर से कोई आधिकारिक सूचना दी गई और न ही किसी प्रकार का ईमेल या मैसेज भेजकर अपडेट दिया गया। कुछ यात्रियों ने यह भी बताया कि सर्वर की समस्या कल से ही चल रही है, पर कंपनी ने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

दिल्ली की यात्री संध्या ने बताया कि वह कल देहरादून से दिल्ली पहुंची थीं और आज विशाखापट्टनम के लिए उनकी कनेक्टिंग फ्लाइट थी। सर्वर में खराबी और फ्लाइट के लेट होने से उनका कनेक्शन टूट गया और उन्हें दोबारा टिकट बुक करनी पड़ी। उन्होंने कहा, "ना कोई मैसेज आया, ना कोई घोषणा हुई। लोग बस काउंटर के बाहर खड़े हैं और कोई जवाब नहीं मिल रहा।"

वहीं, एअर इंडिया की इस तकनीकी गड़बड़ी का असर अन्य एयरलाइनों पर भी दिखाई दिया। दिल्ली एयरपोर्ट पर हवाई यातायात धीमा पड़ गया, जिससे इंडिगो, विस्तारा और स्पाइसजेट जैसी एयरलाइनों की उड़ानें भी प्रभावित हुईं। इंडिगो ने शाम को एक एडवाइजरी जारी करते हुए कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर असामान्य भीड़ और एयर ट्रैफिक की वजह से उड़ान संचालन में देरी हो सकती है। कंपनी ने यात्रियों को सलाह दी कि वे अपनी यात्रा से पहले वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर उड़ान की वास्तविक स्थिति जांच लें।

सूत्रों के अनुसार, एअर इंडिया के सर्वर में यह समस्या उसके सेंट्रल डाटा नेटवर्क से जुड़ी है, जो टिकटिंग, चेक-इन और बैगेज सिस्टम को नियंत्रित करता है। तकनीकी विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की गड़बड़ी का कारण सॉफ्टवेयर अपडेट में हुई त्रुटि या नेटवर्क लिंक का बाधित होना हो सकता है।

वहीं, यात्रियों का धैर्य टूटने लगा है। एयरपोर्ट पर घंटों इंतजार के बाद कई लोगों ने टिकट रद्द कराने का निर्णय लिया। कुछ यात्रियों ने इसे एअर इंडिया के "खराब प्रबंधन" का उदाहरण बताया। अब देखना यह है कि एयरलाइन अपनी तकनीकी गड़बड़ी को कितनी जल्दी ठीक कर पाती है, क्योंकि फिलहाल देश के सबसे व्यस्त एयरपोर्ट पर

मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन-पूजन किए

मुख्यमंत्री ने गुरु ग्रंथ साहिब की पूजा-अर्चना कर राज्य के नागरिकों की सुख, समृद्धि, शांति और विकास के लिए अरदास की

(जीएनएस)। गांधीनगर : मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने श्री गुरु नानक जी की 556वीं जयंती के पावन पर्व पर बुधवार को गांधीनगर जिले के पोर गांव में स्थित गुरुद्वारे में सिख परिवारों की ओर से आयोजित सत्संग, कीर्तन और पूजा में भावपूर्वक भाग लिया।

मुख्यमंत्री ने गुरुद्वारा में गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन किए और पूजा-अर्चना कर राज्य के सभी नागरिकों की सुख-समृद्धि, शांति और विकास के लिए अरदार की।

इस अवसर पर गुरुद्वारा के मुख्य सेवक गुरुप्रीत सिंह ढिल्लों तथा परमजीत कौर छाबड़ा ने मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल को अंग वस्त्र और स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति भेंट कर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री और महानुभावों ने गुरुद्वारा में इस शुभ अवसर पर आयोजित लंगर में प्रसाद वितरण की सेवा भी की।

ऊर्जा एवं पेट्रोकेमिकल्स मंत्री श्री ऋषिकेश पटेल, महापौर श्रीमती मीराबेन पटेल, विधायक श्रीमती रीटाबेन पटेल और श्री अल्पेश ठाकोर भी गुरुद्वारा में दर्शनार्थ मौजूद रहे।

पोरबंदर–सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन को लिंगमपल्ली स्टेशन पर अस्थायी ठहराव की सुविधा

(जीएनएस)। त्योहारों के दौरान यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा भीड़ प्रबंधन के उद्देश्य से रेल प्रशासन द्वारा लिंगमपल्ली (LPI) स्टेशन पर कुछ ट्रेनों का अस्थायी ठहराव प्रदान किया गया है। यह सुविधा आगामी 06 माह की अवधि के लिए, तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल, 2026 तक लागू रहेगी।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि इस अवधि में निम्नलिखित ट्रेनें लिंगमपल्ली स्टेशन पर अस्थायी रूप से ठहरेंगी –

1.ट्रेन संख्या 20967 सिकंदराबाद–पोरबंदर एक्सप्रेस
लिंगमपल्ली स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय – 15.39/15.40 बजे

2.ट्रेन संख्या 20968 पोरबंदर–सिकंदराबाद एक्सप्रेस
लिंगमपल्ली स्टेशन पर आगमन/प्रस्थान समय – 06.14/06.15 बजे

यह अस्थायी ठहराव यात्रियों की सुविधा के दृष्टिगत किया गया है, जिससे क्रिसमस, नववर्ष एवं संक्रांति पर्वों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। इस निर्णय से यात्रियों को लिंगमपल्ली स्टेशन से यात्रा करने में सुगमता एवं सुविधा प्राप्त होगी।

19 नवंबर को पोरबंदर से चलने वाली पोरबंदर-शालीमार सुपरफास्ट ट्रेन सांतरागाछी जं. स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट होगी

(जीएनएस)। रेलवे प्रशासन द्वारा शालीमार स्टेशन पर यार्ड रिमॉडलिंग से संबंधित इंजीनियरिंग कार्य किए जाने के कारण पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल से चलने वाली पोरबंदर-शालीमार सुपरफास्ट ट्रेन को सांतरागाछी जं. स्टेशन पर शॉर्ट टर्मिनेट एवं शॉर्ट ओरिजिनेट किया जाएगा।

वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि —

19 नवंबर, 2025 को पोरबंदर से चलनवे वाली ट्रेन संख्या 12905 पोरबंदर-शालीमार सुपरफास्ट की यात्रा सांतरागाछी जं. स्टेशन पर ही समाप्त होगी।

इसी प्रकार, 21 नवंबर, 2025 को शालीमार से चलने वाली ट्रेन संख्या 12906 शालीमार-पोरबंदर सुपरफास्ट की यात्रा सांतरागाछी जं. स्टेशन से ही प्रारंभ होगी। भावनगर मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने यात्रियों से अनुरोध किया है कि वे उक्त तिथियों में अपनी यात्रा से पूर्व गाड़ियों की स्थिति एवं समय संबंधी नवीनतम जानकारी के लिए NTES ऐप अथवा भारतीय रेल की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी प्राप्त करें। आरक्षित यात्रियों को इस परिवर्तन की सूचना SMS अलर्ट के माध्यम से प्रदान की जाती है। रेलवे प्रशासन यात्रियों से सहयोग की अपील करता है एवं किसी भी असुविधा के लिए खेद व्यक्त करता है।

रेलवे के पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर 30 नवम्बर 2025 तक जीवन प्रमाणपत्र अनिवार्य रूप से जमा कराएं

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वित्त प्रबंधक श्री मोहित पंचाल ने जानकारी दी है कि रेलवे के सभी पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) दिनांक 30 नवम्बर 2025 तक अनिवार्य रूप से जमा कराना आवश्यक है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पेंशनरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए तथा बैंकों में लंबी कतारों और वृद्ध पेंशनरों को होने वाली असुविधा से बचाने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा "जीवन

प्रमाण (Jeevan Pramaan)" नामक एक डिजिटल एप्लिकेशन विकसित किया गया है। इस एप्लिकेशन के माध्यम से पेंशनर अपने घर बैठे ही डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर सकते हैं तथा प्रमाणपत्र की प्रति ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं।

यदि किसी पेंशनर को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने में किसी प्रकार की कठिनाई आती है, तो वे सहायता हेतु भावनगर परा स्थित मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के लेखा विभाग से संपर्क कर सकते हैं।

मंडल रेल प्रबंधक श्री दिनेश वर्मा ने सभी पेंशनरों एवं पारिवारिक पेंशनरों से अनुरोध किया है कि वे अपना जीवन प्रमाणपत्र निर्धारित तिथि तक जमा कराएं, ताकि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए।

पश्चिम रेलवे के स्थापना दिवस पर रंग बिरंगी रोशनी से सजे वडोदरा मंडल के स्टेशन भवन

(जीएनएस)। 2025 को पश्चिम रेलवे ने अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया। अपनी शुरुआत के बाद से पश्चिम रेलवे ने राष्ट्र की सेवा में अपनी 70 से अधिक वर्षों की यात्रा में कई मील के पत्थर हासिल किए हैं। इस अवसर पर वडोदरा मंडल के प्रधान कार्यालय सहित मंडल की सभी प्रमुख स्टेशन बिल्डिंगों वडोदरा, एकतानगर, प्रतापनगर, मकरपुरा, डभोई आदि स्टेशनो को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया। पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल के जनसंपर्क अधिकारी श्री अनुभव सक्सेना द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी (बीबी एंड सीआई) का गठन 1855 में किया गया था, जिसकी शुरुआत गुजरात राज्य में पश्चिमी तट पर अंकलेश्वर से उत्राण तक 29 मील ब्रॉड गेज ट्रैक के निर्माण के साथ हुई थी एवं इसका मुख्यालय सूरत में था। उसी वर्ष 21 नवम्बर, 1855 को कंपनी ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ सूरत से बड़ौदा और अहमदाबाद तक एक रेलवे लाइन बनाने के लिए एक समझौता किया। इस के साथ ही पश्चिमी बंदरगाह में गुजरात में पैदा की जाने वाली कपास की भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उत्राण (सूरत के उत्तर) से तत्कालीन बॉम्बे तक एक लाइन शुरू करने के लिए एक और अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए थे। इसके अगले वर्ष लाइन पर काम शुरू हुआ और उत्राण से बॉम्बे में ग्रांट रोड स्टेशन तक की लाइन को आधिकारिक तौर पर 28 नवम्बर, 1864 को खोला गया जिसके द्वारा मुंबई में पश्चिमी लाइन की शुरुआत हुई।

श्री सक्सेना ने आगे बताया कि अपने वर्तमान स्वरूप में पश्चिम रेलवे 5 नवम्बर, 1951 को अपनी अग्रदूत, तत्कालीन बॉम्बे, बड़ौदा और सेंट्रल इंडिया रेलवे कंपनी (बीबी और सीआई) के अन्य स्टेट रेलवे जैसे सौराष्ट्र, राजपुताना और जयपुर के साथ विलय से अस्तित्व में आयी। 1850 के दशक में ब्रिटिश काल में अपने जन्म के बाद से पश्चिम रेलवे ने अपनी लंबी यात्रा में बार-बार अपनी श्रेष्ठता साबित की है।

महेसाणा स्टेशन का पुनर्विकास कार्य तेजी से प्रगति पर, यात्रियों को मिलेगी अत्याधुनिक सुविधाएँ और बेहतर यात्रा अनुभव

(जीएनएस)। पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल पर महेसाणा रेलवे स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना (ABSS) के तहत पुनर्विकास तेजी से किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्टेशन को न केवल यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित करना है, बल्कि इसे शहर के विकास, कनेक्टिविटी और आर्थिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र भी बनाना है। पुनर्विकास के बाद मेहसाणा स्टेशन एक मल्टीमॉडल ट्रांजिट हब के रूप में उभरेगा, जहाँ आधुनिकता, सुविधा और सौंदर्य का सुंदर संगम दिखाई देगा।

नया स्टेशन भवन (पूर्व दिशा) – निर्माणाधीन

- महेसाणा स्टेशन के पूर्व दिशा में स्थित नए स्टेशन भवन का निर्माण कार्य तेज़ी से चल रहा है। भवन के फसाड का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिससे स्टेशन का बाहरी दृश्य अधिक आधुनिक और आकर्षक लगेगा।
- सर्कुलेटिंग एरिया पोर्च, वेटिंग रूम, बुकिंग ऑफिस, टिकट चेकिंग स्टाफ ऑफिस, पूछताछ कार्यालय और वाहन संचालन हेतु सुचारु व्यवस्थाएँ शामिल होंगी।
- अधिकारियों के लिए विश्रामगृह, 03 रिटायरिंग रूम, डॉर्मिटरी, सीसीटीवी निगरानी प्रणाली, और स्वच्छ शौचालयों की व्यवस्था भी की जा रही है ताकि यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों दोनों को सुविधा मिल सके।

प्रमुख कार्य एवं प्रगति की स्थिति

- मुख्य प्रवेश द्वार पर टू-व्हीलर और फोर-व्हीलर पार्किंग का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है।
- दूसरे प्रवेश द्वार के स्टेशन भवन में बुकिंग ऑफिस तथा एसी/नॉन-एसी वेटिंग हॉल का कार्य प्रगति पर है।
- यात्रियों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 40 फीट चौड़ा रूफ प्लाज़ा बनाया जा रहा है, जो स्टेशन के दोनों ओर सुगम कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। यह रानी कमलापती स्टेशन पर बनाए गए रूफ प्लाज़ा के अनुभव के आधार पर बनाया जा रहा है।
- प्लेटफॉर्म 4 एवं 5 पर शेल्टर निर्माण का कार्य पूरा हो चुका है, और इन्हें दिव्यांगजन-अनुकूल बनाया गया है।

आधुनिक यात्री सुविधाएँ

- महेसाणा स्टेशन के पुनर्विकास के बाद यात्रियों को अनेक सुविधाजनक एवं अत्याधुनिक सुविधाएँ प्राप्त होंगी।
- कुल 08 प्लेटफॉर्म और 12 रेल लाइनें, जिनमें से 02 डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC) के लिए आरक्षित हैं।
- स्टेशन पर 02 फुट ओवर ब्रिज और 04 लिफ्ट्स का निर्माण किया जा रहा हैं।
- यात्रियों के आराम हेतु एसी, नॉन-एसी और महिला प्रतीक्षालय बनाए जा रहे हैं।
- प्रत्येक प्लेटफॉर्म पर 28-28 स्टेनलेस स्टील बेंच लगाई जा रही हैं, साथ ही कोच गाइडेंस सिस्टम प्लेटफॉर्म नं. 1, 4/5 और 6/7 पर लगाए जा रहे है।
- यात्रियों की सुविधा के लिए फूड प्लाज़ा, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल, जन औषधि केंद्र, एटीएम, एटीवीएम, लगेज ट्रॉली तथा व्हीलचेयर की व्यवस्था की जा रही है।
- स्टेशन परिसर में हाइ-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं ताकि सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
- डॉर्मिटरी, रिटायरिंग रूम, बुकिंग ऑफिस और पूछताछ केंद्र का आधुनिकीकरण किया गया है।
- यात्रियों को एक अनोखा अनुभव प्रदान करने के लिए "रेस्टोरेंट ऑन व्हील्स" की स्थापना की योजना भी प्रस्तावित है।

ट्रेनों का संचालन एवं यातायात

- महेसाणा स्टेशन पश्चिम रेलवे का एक प्रमुख स्टेशन है जहाँ—
- प्रतिदिन 38 सुपरफास्ट, 23 मेल/एक्सप्रेस तथा 10 लोकल ट्रेनें रुकती हैं।
- 06 ट्रेनें मेहसाणा से आरंभ होती हैं।
- प्रतिदिन लगभग 12,000 यात्री इस स्टेशन से यात्रा करते हैं।

यात्रियों एवं क्षेत्र के लिए लाभ

महेसाणा स्टेशन के पुनर्विकास से यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और आधुनिक यात्रा अनुभव प्राप्त होगा। स्टेशन परिसर में विकसित की जा रही नई सुविधाएँ स्थानीय व्यापार, पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देंगी। इस परियोजना से शहर और आसपास के क्षेत्रों को बेहतर रेल कनेक्टिविटी प्राप्त होगी, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी। महेसाणा स्टेशन का यह कायाकल्प स्थानीय निवासियों के लिए आर्थिक प्रगति, सुविधा और गर्व का नया अध्याय सिद्ध होगा, जो "नए भारत के आधुनिक रेलवे स्टेशन" की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

किसानों के हित में गुजरात सरकार का महत्वपूर्ण निर्णय

- मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में 9 नवंबर से शुरू होगी मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की समर्थन मूल्य पर खरीद : कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी
- किसानों से समर्थन मूल्य पर लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन की खरीदी की जाएगी
- राज्य में मूंगफली के बंपर उत्पादन को ध्यान में रखकर प्रति किसान 125 मन मूंगफली की खरीदी करने का उदारतम निर्णय

(जीएनएस)। गांधीनगर : कृषि मंत्री श्री जीतूभाई वाघाणी ने बुधवार को गांधीनगर में गुजरात सरकार द्वारा किसानों के हित में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के किसानों को उनकी उपज के लाभकारी मूल्य के साथ-साथ आर्थिक सुरक्षा भी मिल सके, इसके लिए मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल के मार्गदर्शन में गुजरात में आगामी 9 नवंबर से समर्थन मूल्य पर मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन जैसी खरीफ फसलों की खरीद शुरू करने का निर्णय किया गया है।

कृषि मंत्री ने इस संदर्भ में कहा कि देश के किसानों को आर्थिक नुकसान से बचाने के लिए प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में चालू वर्ष में समर्थन मूल्य में उल्लेखनीय वृद्धि करने का निर्णय किया गया है। गत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में मूंगफली के मूल्य में प्रति क्विंटल 480 रुपए, उड़द के मूल्य में 400 रुपए और सोयाबीन के मूल्य में प्रति क्विंटल 436 रुपए की वृद्धि की गई है। मूल्य में बढ़ोतरी के साथ-साथ लाभकारी मूल्य मिलने से किसानों को इसका अधिकतम लाभ मिलेगा।

श्री वाघाणी ने कहा कि राज्य में प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान के तहत चालू सीजन में राज्य के किसानों से लगभग 15,000 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य की मूंगफली, सोयाबीन, उड़द और मूंग की खरीदी करने का आयोजन किया गया है। इससे राज्य के किसानों को अपनी उपज कम बाजार मूल्य पर नहीं बेचनी पड़ेगी।

राज्य में चालू वर्ष में मूंगफली के बंपर उत्पादन को ध्यान में रखते हुए सरकार के मानदंडों के अनुसार प्रति किसान 125 मन मूंगफली खरीदने का उदारतम निर्णय लिया गया है।

कृषि मंत्री ने कहा कि गुजरात में खरीफ फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए राज्य में कुल बुवाई क्षेत्र और उत्पादन को ध्यान में रखते हुए मूंगफली, मूंग, उड़द और सोयाबीन के लिए 300 से अधिक खरीद केंद्र अनुमोदित किए गए हैं, जहां समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर केंद्रों की संख्या और भी बढ़ाई जाएगी। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा खरीफ फसलों की बुवाई से पहले ही समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी गई थी। जिसके अनुसार मूंगफली का समर्थन मूल्य 7263 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग का समर्थन मूल्य 8768 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द का समर्थन मूल्य 7800 रुपए प्रति क्विंटल और सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5328 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया गया है।

गिरनार परिक्रमा पर रोक की वजह से वेरावल-गांधीग्राम स्पेशल ट्रेन निरस्त

(जीएनएस)। जूनागढ़ में लगने वाले परिक्रमा मेले पर स्थानीय प्रशासन द्वारा रोक लगाए जाने के कारण पश्चिम रेलवे द्वारा भावनगर मंडल के वेरावल-गांधीग्राम के बीच चलने वाली वेरावल-गांधीग्राम स्पेशल ट्रेन को निरस्त कर दिया गया है। भावनगर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक श्री अतुल कुमार त्रिपाठी ने बताया की इस स्पेशल ट्रेन की सेवाएं 11 नवंबर, 2025 तक उपलब्ध होनी थी, परन्तु अब इस सुविधा को तत्काल प्रभाव से (05 नवंबर, 2025 से) निरस्त करने का निर्णय लिया गया है।

निरस्त की जाने वाली ट्रेनें:

1. ट्रेन संख्या 09226 (वेरावल-गांधीग्राम)
2. ट्रेन संख्या 09225 (गांधीग्राम-वेरावल)

यात्रियों से अनुरोध है कि यात्रा की योजना बनाते समय उक्त परिवर्तनों पर ध्यान दें। असुविधा के लिए रेलवे प्रशासन खेद व्यक्त करता है।

डेयरी और MSME के हितों के लिए भारत प्रतिबद्ध: पीयूष गोयल

(जीएनएस)। वेलिंगटन। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बुधवार को कहा कि भारत अपने सभी मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) में डेयरी, कृषि और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएमई) जैसे संवेदनशील क्षेत्रों के हितों की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। न्यूजीलैंड की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे गोयल ने यह बात ऑकलैंड में आयोजित भारत-न्यूजीलैंड व्यापार मंच को संबोधित करते हुए कही।

उन्होंने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौते पर चौथे दौर की बातचीत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि वार्ता के दौरान एक-दूसरे की संवेदनशीलताओं और घरेलू आर्थिक संरचना का पूरा सम्मान किया जाएगा। गोयल ने कहा कि आने वाले चरणों में यह वार्ता और तेज़ी से आगे बढ़ेगी, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों को नई दिशा मिलेगी। वाणिज्य मंत्री ने साफ कहा कि भारत ने अब तक किसी भी एफटीए में डेयरी या कृषि क्षेत्र में किसी देश को शुल्क रियायत नहीं दी है। उन्होंने कहा कि किसानों और एमएसएमई क्षेत्र के हित भारत के लिए सर्वोपरि हैं और इन पर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। गोयल ने कहा, "हमारा लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैश्विक व्यापार में भागीदारी बढ़ाने के साथ-साथ हमारे स्थानीय उद्योग, किसान और उद्यमी सुरक्षित रहें और उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त मिले।" उन्होंने न्यूजीलैंड के वाणिज्य मंत्री टॉड मैक्ले के साथ हुई अपनी वार्ता को "बेहद सकारात्मक और रचनात्मक" बताते हुए कहा कि यह संवाद दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक साझेदारी की मजबूत नींव रखेगा। गोयल ने कहा कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच न केवल व्यापारिक, बल्कि तकनीकी और निवेश संबंधों को भी गहराई देने पर जोर दिया जा रहा है।

भारत-अमेरिका व्यापार वार्ता के बारे में पूछे जाने पर गोयल ने कहा कि दोनों देशों के बीच रचनात्मक बातचीत लगातार जारी है। उन्होंने बताया कि कई जटिल विषयों पर ठोस प्रगति हुई है और दिशा सकारात्मक है। गोयल ने कहा, "भारत के वैश्विक व्यापार संबंधों का मकसद किसी देश के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना नहीं, बल्कि पारस्परिक लाभ और स्थायी विकास को सुनिश्चित करना है।"

उन्होंने यह भी बताया कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच कृषि, रक्षा, शिक्षा, अंतरिक्ष, पर्यटन, डेयरी मशीनरी और कृषि प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाएँ मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि एक मजबूत भारत-न्यूजीलैंड एफटीए से दोनों देशों के उद्योगों, किसानों और नागरिकों के लिए नए अवसर पैदा होंगे।

ऑकलैंड में आयोजित भारतीय समुदाय के एक विशेष कार्यक्रम में पीयूष गोयल ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन और वाणिज्य मंत्री टॉड मैक्ले के साथ मंच साझा किया। इस दौरान गोयल ने दोनों नेताओं को गले लगाकर भारत-न्यूजीलैंड की बढ़ती मित्रता और पारस्परिक सम्मान का संदेश दिया। उन्होंने प्रवासी भारतीय समुदाय की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि भारतीय मूल के लोग दुनिया में भारत की संस्कृति, मूल्य और उद्यमशीलता का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार दुनिया भर में बसे भारतीयों की भावनात्मक, सांस्कृतिक और आर्थिक साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

जालंधर के अंबेडकर नगर पर मंडरा रहा बुलडोज़र का खतरा: 800 मकान तोड़फोड़ की जद में, अदालत की अगली सुनवाई 14 नवंबर को

(जीएनएस)। जालंधर। पंजाब के जालंधर जिले में बसे अंबेडकर नगर की किस्मत एक बार फिर अधर में लटक गई है। अदालत द्वारा तोड़फोड़ के आदेश जारी होने के बाद यहां के लगभग 800 मकान खतरे में आ गए हैं। पावरकॉम की ज़मीन पर बसे इस इलाके का विवाद बीते दो दशकों से जारी है, और अब एक बार फिर यह मुद्दा राजनीतिक और सामाजिक दोनों मोर्चों पर गर्मा गया है।

यह मामला साल 2003 से चल रहा है, जब बिजली बोर्ड (पावरकॉम) ने अपनी ज़मीन पर अतिक्रमण हटाने के लिए अदालत में याचिका दायर की थी। यह ज़मीन मूल रूप से 1969 में सीमा सुरक्षा बल (BSF) के लिए अधिग्रहित की गई थी, लेकिन 1997 में सरकार ने इसमें से 65.50 एकड़ भूमि बिजली विभाग को कर्मचारियों की कॉलोनी और स्टोर निर्माण के लिए दे दी। विभाग ने वहाँ कुछ इमारतें बनाईं, लेकिन बाकी ज़मीन खाली पड़ी रही। इसी बीच, खाली ज़मीन पर धीरे-धीरे कब्ज़ा शुरू हुआ और वहां “डॉ. बी. आर. अंबेडकर नगर” नामक बस्ती बस गई, जहां अब 800 से अधिक परिवार रह रहे हैं।

बिजली बोर्ड ने 2014 में यह मामला जीत लिया था, जब जालंधर कोर्ट ने पावरकॉम के पक्ष में फैसला सुनाया। हालांकि, अंबेडकर नगर के निवासियों ने 2015 में फैसले के खिलाफ अपील दायर की, लेकिन उस पर वर्षों तक सुनवाई नहीं हो सकी। अब अदालत ने पुलिस प्रशासन को 3 अक्टूबर, 2025 तक कब्ज़ा लेने का वारंट जारी कर दिया है और अगली सुनवाई 14 नवंबर को तय की गई है।

इस बीच, इस मामले में नया मोड़ तब आया जब अंबेडकर नगर के प्रमुख याचिकाकर्ता कृपाल सिंह का निधन हो गया, जिससे केस की पैरवी कमजोर हो गई। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी ने इस विवाद को अपने हाथ में ले लिया है। पार्टी के जालंधर सेंट्रल प्रभारी नितिन कोहली के नेतृत्व में 10 सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो मुख्यमंत्री भगवंत मान के समक्ष इस मुद्दे को उठा चुकी है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि यह सिर्फ अतिक्रमण का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और पुनर्वास से जुड़ा प्रश्न है। नितिन कोहली ने कहा कि “जब इन परिवारों को आधार कार्ड, बिजली, पानी और सीवरेज कनेक्शन दिए गए, तब सरकारी विभागों ने ही उन्हें नागरिक अधिकारों के दायरे में मान्यता दी थी। अब उन्हें अचानक अवैध बताना अन्याय है।”

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि कांग्रेस के समय में भी इसी इलाके को बचाने के लिए कई बार हस्तक्षेप हुआ था। उस वक्त भी स्थानीय नेताओं ने निवासियों को अस्थायी राहत दिलाई थी। अब वही परंपरा आम आदमी पार्टी के संरक्षण में दोहराई जा रही है।

हालांकि, पावरकॉम का रुख सख्त है। विभाग का कहना है कि यह ज़मीन विभागीय संपत्ति है और अदालत ने साफ तौर पर कब्ज़ा खाली कराने का आदेश दिया है। पावरकॉम के एक अधिकारी ने कहा, “हमने वर्षों तक इन्हें हटाने की कार्रवाई टाल दी थी, लेकिन अब अदालत के आदेशों का पालन अनिवार्य है। अगर आदेश नहीं माने गए तो विभाग पर अवमानना की कार्यवाही हो सकती है।”

वहीं, अंबेडकर नगर के लोग भय और अनिश्चितता में हैं। निवासी गुरदीप सिंह का कहना है, “हम पिछले 20 साल से यहां रह रहे हैं, सरकार ने हमें बिजली-पानी दिया, वोटर कार्ड बनाए। अब अचानक कह रहे हैं कि यह ज़मीन अवैध है। हमें कहीं और बसाने की व्यवस्था किए बिना कैसे घर तोड़े जाएंगे?”

इस मामले में दिलचस्प पहलू यह भी है कि पावर वर्क्स की ज़मीन, जो अंबेडकर नगर के ठीक सामने है, वहां भी हाल ही में अतिक्रमण शुरू हुआ है। परंतु वहां विभाग ने अभी तक कोई आपत्ति नहीं जताई, बल्कि अब विचार कर रहा है कि वह ज़मीन अतिक्रमणकारियों को सरकारी दरों पर बेच दी जाए। इससे अंबेडकर नगर के लोगों में और असंतोष फैल गया है।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, फिलहाल अंबेडकर नगर का विस्तृत नक्शा तैयार किया जा रहा है और अतिक्रमण की सटीक सीमाओं की पहचान की जा रही है। सरकार पर दबाव है कि वह या तो इस क्षेत्र को नियमित करे या प्रभावित परिवारों को वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराए।

अब सभी की नजर 14 नवंबर को अदालत की सुनवाई पर टिकी है, जहां यह तय होगा कि क्या वास्तव में बुलडोज़र अंबेडकर नगर में चलेगा या फिर एक बार फिर राजनीति इस बस्ती को कुछ वर्षों के लिए बचा लेगी। फिलहाल 800 परिवार सांसें थामे उस तारीख़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जब उनके सिर पर मंडराता विध्वंस का साया या तो हटेगा—या स्थायी रूप से टूट पड़ेगा।

राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे, देशभर में उत्सव की तैयारी; प्रधानमंत्री मोदी करेंगे दिल्ली से नेतृत्व

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रगीत ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के ऐतिहासिक अवसर पर देश एकजुट होकर अपनी सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देने जा रहा है। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने देशभर में बड़े स्तर पर उत्सव मनाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सात नवंबर को राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित मुख्य समारोह में भाग लेंगे, जहां सामूहिक रूप से ‘वंदे मातरम’ का गायन किया जाएगा।

भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुघ ने बुधवार को पार्टी मुख्यालय में बताया कि यह आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि भारत की आत्मा और स्वाभिमान का उत्सव है। उन्होंने कहा, “वंदे मातरम केवल गीत नहीं है, यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम का उद्घोष रहा है, जिसने देशवासियों में आत्मबल और देशभक्ति की ज्वाला जगाई। आज जब इसके 150 वर्ष पूरे हो रहे हैं, तो यह हर भारतीय के लिए गर्व का क्षण है।”

चुघ ने बताया कि सात नवंबर से लेकर 26 नवंबर — यानी संविधान दिवस तक — देश के हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में विशेष आयोजन होंगे। सात नवंबर को देश के 150 प्रमुख स्थलों पर एक साथ ‘वंदे मातरम’ का सामूहिक गायन होगा। इसके बाद लोगों से स्वदेशी उत्पादों के उपयोग की शपथ दिलाई जाएगी, ताकि ‘आत्मनिर्भर भारत’ की भावना को भी बल मिले। इस कार्यक्रम को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। पार्टी की राज्य इकाइयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने राज्यों में ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों पर यह आयोजन करें। कई जगहों पर स्कूलों, कॉलेजों, सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी भागीदारी के लिए आमंत्रित किया गया है।

भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने गुरुग्राम में संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री मोदी स्वयं दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाले मुख्य समारोह में उपस्थित रहेंगे और राष्ट्रगीत के सामूहिक गायन में भाग लेंगे। उन्होंने कहा, “यह केवल राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि राष्ट्र के गौरव का पर्व है। यह गीत हर भारतीय को यह याद दिलाता है कि भारत माता की सेवा ही हमारा सर्वोच्च धर्म है।”

गौरतलब है कि ‘वंदे मातरम’ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा 1875 में लिखा गया था, जो बाद में भारत की आजादी के संघर्ष का प्रतीक बन गया। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी गीत से प्रेरणा पाकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष को तेज किया था।

सात नवंबर का यह दिन न केवल राष्ट्रगीत के गौरवशाली इतिहास को याद करने का अवसर होगा, बल्कि यह भी संदेश देगा कि आधुनिक भारत अपनी सांस्कृतिक जड़ों और मूल्यों से जुड़ा रहकर आगे बढ़ रहा है। जब प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली से राष्ट्रगीत का गायन करेंगे, तो देश के कोने-कोने में करोड़ों भारतीय एक स्वर में “वंदे मातरम” का उद्घोष करेंगे — जो भारत माता के प्रति प्रेम, समर्पण और गौरव का प्रतीक बनेगा।

भारत-रोमानिया के बीच नया आर्थिक अध्याय: व्यापार और निवेश बढ़ाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर

(जीएनएस)। नई दिल्ली। भारत और रोमानिया के बीच आर्थिक सहयोग के नए युग की शुरुआत हो गई है। बुधवार को रोमानिया के ब्रासोव शहर में आयोजित “भारत-रोमानिया व्यापार मंच” के दौरान दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर भारत की ओर से केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जबकि रोमानिया की ओर से उच्च स्तरीय अधिकारियों और उद्योग प्रतिनिधियों ने भाग लिया। समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच औद्योगिक साझेदारी को सशक्त करना, निवेश के अवसरों को बढ़ावा देना और नई प्रौद्योगिकियों के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है। इस समझौते से न केवल व्यापारिक गतिविधियों को नई दिशा मिलेगी, बल्कि रक्षा, ऑटोमोबाइल, नवीकरणीय ऊर्जा और सूचना प्रौद्योगिकी जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग के द्वार खुलेंगे।

कार्यक्रम के दौरान जितिन प्रसाद ने भारत की आर्थिक प्रगति और वैश्विक स्तर पर बढ़ते प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत आज दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने रोमानिया के उद्योगपतियों से ‘मेक इन इंडिया’, ‘स्टार्टअप इंडिया’ और उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) जैसी योजनाओं का लाभ उठाने की अपील की। उन्होंने कहा, “भारत का विनिर्माण और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र वैश्विक निवेशकों के लिए अपार अवसर प्रस्तुत करता है। यह समय है जब रोमानियाई उद्योग भारत के विकास सफर का हिस्सा बनें।” वाणिज्य मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, मंच में “भारत में व्यापारिक अवसरों” विषय पर विस्तृत प्रस्तुति दी गई। इसमें औद्योगिक गलियारों, नीतिगत सुधारों, व्यापार सुगमता उपायों और राज्य-स्तरीय निवेश प्रोत्साहनों की जानकारी साझा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने विशेष रूप से बताया कि कैसे भारत का बढ़ता हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर और स्थिर नीति ढांचा विदेशी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार कर रहा है।

कच्छ की कोयल गीता रबारी ने वृंदावन में सुनाया श्रीकृष्ण भजन, संत प्रेमानंद हुए भावविभोर

(जीएनएस)। वृंदावन। राधा-कृष्ण की भक्ति से सुवासित भूमि वृंदावन बुधवार की सुबह एक अद्भुत दृश्य की साक्षी बनी जब गुजरात की प्रसिद्ध लोकगायिका और भजन गायिका गीता रबारी, जिन्हें ‘कच्छ की कोयल’ के नाम से जाना जाता है, ने संत प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम में अपने सुरों से कृष्ण प्रेम का अमृत बरसाया।

सुबह लगभग साढ़े सात बजे परिक्रमा मार्ग स्थित श्रीराधा केलिकुंज आश्रम में जब गीता रबारी पहुंचीं, तो भोर की उस पावन बेला में चारों ओर भजन और नामस्मरण की ध्वनि गूंज रही थी। भक्तों की भीड़ संत प्रेमानंद जी के एकांत वार्ता सत्र का हिस्सा बनने के लिए पहले से ही उपस्थित थी। उसी समय गीता रबारी folded hands के साथ संत के चरणों में पहुंचीं, उन्होंने विनम्रता से आशीर्वाद लिया और फिर अपने मधुर स्वर में श्रीकृष्ण को समर्पित एक भजन गाना शुरू किया।

उनकी आवाज में न केवल संगीत का माधुर्य था, बल्कि उसमें सच्ची भक्ति की आंच भी झलक रही थी। जब उनके कंठ से निकले शब्द “श्याम तेरो नाम अमृत बरसाए, राधे राधे मन मुस्काए” तो वातावरण का हर कण कृष्णमय हो उठा। आश्रम में बैठे सैकड़ों श्रद्धालु उस भक्ति रस में डूब गए। भजन समाप्त होते ही पूरा परिसर “राधे राधे” के जयघोष से गूंज उठा।

संत प्रेमानंद जी महाराज, जो स्वयं श्रीराधारानी के महान साधक माने जाते हैं, भजन के अंत में गीता रबारी की ओर देखते हुए गदगद हो उठे। उन्होंने कहा, “जब भजन आत्मा से निकलता है, तब वह केवल गान नहीं रहता, वह ईश्वर तक पहुंचने का माध्यम बन जाता है। तुम्हारा स्वर हृदय की गहराई से निकला है, इसीलिए यह सीधा मन को छू गया।”

इस दौरान एक विदेशी महिला भी संत प्रेमानंद से मिलने पहुंची। उसने अत्यंत जिज्ञासा से प्रश्न किया, “प्रेम के मार्ग में जो बाधाएं आती हैं, उन्हें कैसे पार किया जा सकता है?”

संत प्रेमानंद ने सहज मुस्कान के साथ उत्तर दिया, “जहां राधा हैं, वहां कोई बाधा नहीं। प्रेम का मार्ग कठिन जरूर है, परंतु वह हर कष्ट को कृपा के रूप में स्वीकार करता है। शरीर पर जो पीड़ा आती है, वह भी प्रेम की परीक्षा है। यदि प्रेमी उस पीड़ा को याद रखे, तो वह प्रेमी नहीं, व्यापारी है। सच्चा प्रेमी हर कष्ट को ‘राधा राधा’ कहकर सह लेता है, क्योंकि प्रेम ही तो आत्मा की परम साधना है।”

उनके इन शब्दों के साथ ही पूरा वातावरण भक्ति और प्रेम से भर गया। गीता रबारी ने भाव-विभोर होकर कहा, “आज मुझे ऐसा लगा मानो मेरे सुरों को स्वयं श्रीकृष्ण ने स्वीकार किया हो। संत प्रेमानंद जी के सामने भजन गाना मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है।”

वृंदावन के उस क्षण ने सभी उपस्थित श्रद्धालुओं को भीतर तक झकझोर दिया। हर चेहरे पर भक्ति की आभा थी, हर आंख में आनंद के आंसू। गीता रबारी जब आश्रम से विदा हुईं, तो भक्तों ने उन्हें बार-बार “राधे राधे” कहकर विदा किया। वह दृश्य मानो राधा-कृष्ण के प्रेम की जीवंत झांकी बन गया था—जहां संगीत, श्रद्धा और प्रेम एकाकार होकर ईश्वर की उपस्थिति का अनुभव करा रहे थे।

प्रेमी संग रची खौफनाक साजिश: पत्नी ने किया पति का कत्ल, रसोई में ही दफनाया शव, एक साल बाद खुला राज

(जीएनएस)। अहमदाबाद। गुजरात की राजधानी में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने लोगों को हिला कर रख दिया। मशहूर फिल्म दृश्यम की कहानी की तरह एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी और शव को अपने ही घर की रसोई में दफन कर पुलिस को पूरे एक साल तक गुमराह करती रही। यह घटना सरखेज फतेहवाड़ी इलाके की है, जहां एक साल से लापता व्यक्ति की तलाश में जुटी पुलिस को अब जाकर उसकी गुमशुदगी के पीछे छिपा भयावह सच मिला।

मृतक की पहचान समीर बिहारी के रूप में हुई है, जो पिछले एक वर्ष से अचानक गायब हो गया था। उसकी पत्नी रूबी ने प्रेमी इमरान के साथ मिलकर एक खौफनाक योजना बनाई थी। इमरान और रूबी के बीच पिछले कुछ समय से अवैध संबंध चल रहे थे, जिसे लेकर पति-पत्नी के बीच अक्सर झगड़ा होता था। इन झगड़ों से परेशान होकर दोनों ने समीर को रास्ते से हटाने की ठान ली। इमरान ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि उसने और रूबी ने मिलकर पहले समीर को बेहोश किया, फिर उस पर चाकू से कई वार किए। हत्या के बाद शव को काटकर घर की रसोई में गड्ढा खोदकर दफना दिया और ऊपर से सीमेंट से प्लास्टर कर दिया, ताकि कोई शक न कर सके। इसके बाद दोनों ने मिलकर कहानी गढ़ी कि समीर किसी काम से बाहर गया है और वापस नहीं लौटा। इस दौरान रूबी पड़ोसियों और रिश्तेदारों से यही कहती रही कि उसका पति किसी विवाद के कारण शहर छोड़कर चला गया है।

पुलिस को शुरू में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। करीब एक वर्ष तक जांच जारी रही, लेकिन जब रूबी के घर बार-बार इमरान का आना-जाना बढ़ा, तो पुलिस को शक हुआ। स्थानीय लोगों ने भी पुलिस को बताया कि समीर के गायब होने के बाद से रूबी और इमरान का रिश्ता खुला-खुला सा हो गया है। पुलिस ने इमरान को पकड़कर जब सख्ती से पूछताछ की, तो उसने पूरी सच्चाई उगल दी। इमरान ने बताया कि उसने “दृश्यम” फिल्म देखकर ही इस हत्या की साजिश रची थी। उसे लगा कि फिल्म की तरह पुलिस को गुमराह करके वह बच जाएगा। लेकिन रसोई के नीचे दफन किए गए शव से उठती हल्की बदबू और आसपास की मिट्टी में हुए बदलाव ने पुलिस को शक की ओर मोड़ा। अपराध शाखा ने टीम भेजकर खुदाई करवाई, और उसी स्थान से समीर के अवशेष बरामद हुए।

जांच अधिकारियों का कहना है कि यह मामला न केवल एक योजनाबद्ध हत्या का उदाहरण है, बल्कि यह भी दिखाता है कि किस तरह फिल्मी सोच अपराधियों को असल जिंदगी में अपराध के लिए प्रेरित कर सकती है। अपराध शाखा ने रूबी और इमरान दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि समीर सीधा-सादा व्यक्ति था और मजदूरी कर परिवार चलाता था। उसकी पत्नी का इमरान के साथ रिश्ता कई महीनों से गांव में चर्चा का विषय था। जब समीर गायब हुआ, तो लोगों को शक जरूर हुआ, लेकिन किसी ने हिम्मत नहीं की कुछ कहने की। अब जब सच सामने आया, तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि हत्या के बाद दोनों ने घर में दफनाने की योजना कैसे बनाई, किसने सीमेंट का काम किया और क्या किसी तीसरे व्यक्ति ने भी इसमें मदद की थी। अपराध शाखा के अधिकारियों ने कहा कि रसोई की खुदाई के दौरान मिले सबूतों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है, ताकि डीएनए रिपोर्ट से मृतक की पहचान की पुष्टि की जा सके। सरखेज का यह पूरा मामला अब गुजरात पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। पुलिस का कहना है कि यह अपराध जितना क्रूर है, उतना ही चालाकी से अंजाम दिया गया था।

मंगोलिया से सकुशल लौटे 228 भारतीय यात्री, एयर इंडिया की विशेष उड़ान ने निभाई जिम्मेदारी का मिशन

(जीएनएस)। नई दिल्ली। मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में फंसे 228 भारतीय यात्रियों को आखिरकार सुरक्षित स्वदेश लाया गया। एयर इंडिया की विशेष राहत उड़ान ने इन सभी यात्रियों को बुधवार सुबह दिल्ली एयरपोर्ट पर उतारा, जिससे एक तनावपूर्ण इंतजार का अंत हुआ। यह विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जो मंगलवार दोपहर उलानबटार के लिए रवाना हुआ और बुधवार सुबह 8:24 बजे दिल्ली पहुंच गया।

ये सभी यात्री दरअसल सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही नियमित उड़ान AI174 के थे। सोमवार को इस विमान को तकनीकी कारणों से मंगोलिया की राजधानी उलानबटार में आपात स्थिति में डायवर्ट करना पड़ा था। अप्रत्याशित मोड़ के बाद यात्रियों को मंगोलिया में रोकना पड़ा क्योंकि विमान की जांच और तकनीकी सुधार में समय लगना था। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और देखभाल कंपनी की सर्वोच्च प्राथमिकता थी। उन्होंने बताया, “उलानबटार में फंसे हमारे यात्रियों और चालक दल को राहत विमान के माध्यम से सुरक्षित दिल्ली लाया गया है। इस दौरान सभी यात्रियों को स्थानीय प्रशासन और भारतीय दूतावास के सहयोग से आवश्यक सहायता और आवास की व्यवस्था उपलब्ध कराई गई।”

एयर इंडिया ने विशेष रूप से मंगोलिया के अधिकारियों, भारत सरकार, डीजीसीए और स्थानीय दूतावास का आभार व्यक्त किया, जिनके सहयोग से यह जटिल राहत अभियान सुचारू रूप से पूरा हो सका। प्रवक्ता ने कहा, “यह ऑपरेशन हमारे अंतरराष्ट्रीय सहयोग और जिम्मेदार वायुसेवा की भावना का उदाहरण है। कठिन परिस्थितियों में भी हमने यात्रियों को सुरक्षित और समय पर घर पहुंचाने का वादा निभाया।” जानकारी के अनुसार, सैन फ्रांसिस्को से रवाना हुआ विमान एशिया के ऊपर उड़ान के दौरान तकनीकी खामी का शिकार हो गया था, जिसके चलते पायलट ने एहतियातन मार्ग बदलकर निकटतम सुरक्षित हवाई अड्डे उलानबटार में उतरने का निर्णय लिया। वहां उतरने के बाद विमान की जांच और मरम्मत की प्रक्रिया शुरू की गई। यात्रियों ने मंगोलिया में फंसे रहने के दौरान एयर इंडिया और भारतीय दूतावास के प्रयासों की सराहना की। दिल्ली पहुंचने पर कई यात्रियों ने राहत की सांस लेते हुए कहा कि विमान दल ने “तनावपूर्ण माहौल में भी पूरी पेशेवर जिम्मेदारी निभाई और यात्रियों को सुरक्षित रखा।”

दो-तिहाई बहुमत के साथ राजग की बनेगी सरकार: राजनाथ सिंह

(जीएनएस)। पटना/बांका। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बांका में आयोजित एक विशाल जनसभा में दावा किया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) राज्य में दो-तिहाई बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार ने विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं और जनता अब स्थिरता तथा सुशासन को बरकरार रखना चाहती है। राजनाथ सिंह ने विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस और राजद पर आरोप लगाया कि ये दल सीमावर्ती इलाकों और पिछड़े क्षेत्रों के विकास की ओर कभी ध्यान नहीं देते। उन्होंने कहा कि कुछ दल केवल सत्ता प्राप्ति के लिए राजनीति करते हैं, जबकि राजग जनता की भलाई के लिए कार्य करता है। राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सेना का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि भारतीय सेना का कोई धर्म नहीं होता, उसका केवल एक ही धर्म है — “सैन्य धर्म”। उन्होंने कहा कि जब भी भारत पर संकट आया है, सेना ने देश की

मर्यादा को ऊँचा रखा है और उसे राजनीति से दूर रखना आवश्यक है। आरक्षण के मुद्दे पर भी राजनाथ सिंह ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा और राजग आरक्षण के प्रबल समर्थक हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों और वंचितों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार लगातार योजनाएँ चला रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की अर्थव्यवस्था आज वैश्विक स्तर पर नई ऊँचाइयाँ छू रही है।

राजनाथ सिंह ने नीतीश कुमार की ईमानदारी और प्रशासनिक क्षमता की प्रशंसा करते हुए कहा कि उन पर भ्रष्टाचार का कोई दाग नहीं है, जबकि विपक्ष के कई नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लंबित हैं। उन्होंने कहा कि राजद शासन में स्वास्थ्य बजट मात्र 700 करोड़ रुपये था, जो राजग सरकार में बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है — यह बदलाव बताता है कि बिहार सरकार जनता के स्वास्थ्य और विकास के प्रति कितनी गंभीर है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में बिहार का कुल बजट 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक है, जो राज्य की तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का संकेत है। सभा में राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि राजग जाति, धर्म या पंथ के आधार पर राजनीति नहीं करता। उन्होंने कहा कि गठबंधन की प्राथमिकता केवल विकास, शिक्षा, रोज़गार और सुरक्षा पर केंद्रित है। उन्होंने महागठबंधन पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे समाज को बाँटने का काम करते हैं, जबकि राजग उसे जोड़ने में विश्वास रखता है। अंत में रक्षा मंत्री ने कहा कि “ऑपरेशन सिंदूर” अब भी जारी है और यदि कोई आतंकी संगठन भारत की संप्रभुता को चुनौती देने की कोशिश करेगा, तो उसे माकूल जवाब दिया जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बिहार के विकास, स्थिरता और सुशासन के लिए नीतीश कुमार के नेतृत्व में राजग को एक बार फिर भारी बहुमत से जीत दिलाएँ।

16 साल बाद गूंजेगी लोकतंत्र की आवाज़, लखीसराय के नक्सल प्रभावित गांवों में पहली बार लगेगा वोट का मेला

(जीएनएस)। चानन (लखीसराय)। बिहार विधानसभा चुनाव के इस चरण में लोकतंत्र का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। लखीसराय जिले के सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के नक्सल प्रभावित चार गांवों में 16 साल बाद फिर से मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दशकों से हिंसा, भय और प्रशासनिक उपेक्षा के साये में जी रहे इन गांवों के लोगों के लिए यह चुनाव किसी पर्व से कम नहीं है — क्योंकि इस बार उन्हें अपने ही गांव में वोट डालने का अधिकार और सुविधा दोनों मिल रही है।

चानन प्रखंड के पहाड़ी और वन क्षेत्रों में बसे कछुआ और बासकुंड जैसे गांवों में वर्षों तक नक्सलियों का दबदबा रहा। प्रशासनिक अफसरों का यहां आना खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मतदान केंद्रों को मैदानी इलाकों में स्थानांतरित कर दिया गया था। लोगों को वोट डालने के लिए पहाड़ों, पगडंडियों और जंगलों से होकर छह से दस किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता था। कई बार तो सुरक्षा कारणों से मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग ही नहीं कर पाते थे।

लेकिन अब तस्वीर बदल चुकी है। राज्य प्रशासन और चुनाव आयोग के संयुक्त प्रयासों से जब इन इलाकों को “नक्सल-मुक्त क्षेत्र” घोषित किया गया, तो चुनाव आयोग ने ऐतिहासिक निर्णय लेते हुए पुराने मतदान केंद्रों को फिर से उनके मूल स्थानों पर बहाल कर दिया।

चानन प्रखंड के मतदान केंद्र संख्या 407

(सामुदायिक भवन कछुआ) में इस बार 363 मतदाता शामिल होंगे — जिनमें 243 पुरुष और 252 महिलाएं हैं। वहीं मतदान केंद्र संख्या 417 (उत्क्रमित मध्य विद्यालय बासकुंड-कछुआ) में 495 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 186 पुरुष और 177 महिलाएं शामिल हैं।

गांव के बुजुर्ग होइल कोड़ा और भुखो कोड़ा बताते हैं, “पहले हमें जंगल टोला बेलदरिया के प्राथमिक विद्यालय तक पहुंचने में सात-आठ किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। अब गांव में ही बूथ बन गया है, डर भी नहीं है और हम सब वोट डालेंगे।” इसी तरह बासकुंड के बिजो कोड़ा और सुरेश कोड़ा कहते हैं, “महुलिया तक दस किलोमीटर का रास्ता तय करना पड़ता था। अब पहली बार लगता है कि सरकार ने हमें भी नागरिक समझा है।”

इस बार सुरक्षा के भी अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की सख्त निगरानी में मतदान केंद्रों की स्थापना की गई है। पहली बार इन इलाकों में ईवीएम की ‘प’ ध्वनि गूंजेगी — जो भय और हिंसा के वर्षों पुराने सन्नाटे को तोड़ेगी।

लखीसराय प्रशासन के अनुसार, जिले के कुल 56 मतदान केंद्र अब भी नक्सल प्रभावित घोषित हैं, लेकिन स्थिति पहले से कहीं अधिक नियंत्रण में है। अधिकारियों का कहना है कि “यह सिर्फ चुनाव नहीं, बल्कि लोकतंत्र के पुनर्जन्म का प्रतीक है।” स्थानीय निवासियों का उत्साह देखते ही बनता है। महिलाएं कह रही हैं कि वे इस बार सज-धज कर वोट डालने जाएंगी। गांवों में बिजली, पानी, सड़क और शिक्षा जैसी सुविधाओं की चर्चा के साथ “अबकी बार किसे वोट दें” जैसे सवालों पर भी खुलकर बातचीत हो रही है — जो इन इलाकों में लोकतंत्र की गहरी जड़ें जमने का संकेत देता है।

चानन और बासकुंड के ये गांव इस बार सिर्फ एक चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे, बल्कि भय से विश्वास और अलगाव से सहभागिता की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठा रहे हैं।

अब इन गांवों में जो आवाज़ गूंजेगी, वह सिर्फ ईवीएम की क्लिक नहीं, बल्कि लोकतंत्र की पुनर्जागरण ध्वनि होगी।